लखनऊ

बुधवार, 3 जून, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 277

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी हो, वेवजह की विनम्रता दूसरो के अहम को बढ़ावा देती है।

TODAY WEATHER

DAY 42° Hi

NIGHT 29° Low

संक्षेप

अगले तीन दिन में दस्तक दे रहा मानसून, दिल्ली-यूपी समेत 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अनुमान जताया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों के भीतर केरल में प्रवेश कर सकता है। इसके साथ ही विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत 17 राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार, सामान्यत: मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार इसकी दस्तक में हल्की देरी हुई है। हालांकि, वर्तमान मौसमीय परिस्थितियां मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह अनुकूल हैं। इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में 50 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ तूफान और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की आशंका जताई है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 1 से 5 जून के बीच हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है। विशेष रूप से 3 और 4 जून को 50 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 और 4 जून को तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 2 और 5 जून को बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में 6 जून तक गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। राजस्थान में 2 जून को तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि 3 से 5 जून के बीच कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर में 3 से 5 जून के दौरान तेज आंधी और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। 6 जून को भी बारिश के आसार बने हुए हैं।

दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर फटने से मकान गिरा, 6 लोग मलबे से निकाले गए; सर्च-रेस्क्यू जारी

नई दिल्ली। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। भलस्वा डेरी के पास स्थित मुकुंदपुर-ढुढ्ढ के ईशु विहार में एक मकान में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट होने के बाद पूरा घर ढह गया। हादसे के समय मकान में मौजूद कई लोगों के मलबे में दब जाने की आशंका जताई गई, जिसके बाद पुलिस, दमकल विभाग और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, सुबह 9:37 बजे मुकुंदपुर-ढुढ्ढ के ईशु विहार, गली नंबर-1 से धमाके और मकान गिरने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी गिरिराज ने बताया कि शुरुआती जांच में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट को हादसे का कारण माना जा रहा है। विस्फोट के चलते करीब 250 वर्ग गज में फैला एक मंजिला मकान पूरी तरह ढह गया। राहत दल ने अब तक मलबे से 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इनमें दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि दो महिलाएं भी बचाए गए

सीएम योगी ने बदला कुशीनगर के फाजिल नगर का नाम, बोले- 'यूपी से मच्छर-माफिया दोनों खत्म'

» फाजिलनगर का नया नाम भगवान महावीर के नाम पर रखा गया है

» जनसभा के दौरान 424 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

कुशीनगर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के फाजिल नगर का नाम बदलने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम इसे फाजिल क्यों कहें। सीएम योगी ने कहा कि इस जगह को अब पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने फाजिल नगर के विधायक की मांग को मंजूर कर दिया है। विधायक ने इस जगह के नाम को बदलने की मांग की थी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'जैसे यूपी में माफिया खत्म हुआ है, वैसे ही यहां इंसेफेलाइटिस खत्म हो गया है। हमने मच्छरों के साथ-साथ माफिया को भी खत्म कर दिया। मच्छर बीमारियां लाते थे और माफिया बेरोजगारी लाता था। हमने दोनों बीमारियों को ठीक कर दिया। पहले कोई पर्व त्यौहार आता था तो दंगे शुरू हो जाते थे। पडरौना में कैसे दंगे हुए। न्याय मांगने जाते थे तो जेल में डाल दिए जाते थे।

सीएम योगी ने किया विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

दरअसल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कुशीनगर में 424 करोड़ लागत वाली 278 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब कुशीनगर के पास अपना मेडिकल कॉलेज है। साथ ही, इसी शैक्षणिक सत्र से हम कुशीनगर में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन प्रारंभ करने जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के आने के बाद अकेले कुशीनगर में लगभग 90 हजार गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही, 3 लाख 14 हजार से अधिक गरीब परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

विपक्ष पर साधा निशाना

विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिसकी उम्र 25 से कम है वो जंगल पार्टी के आतंक के बारे में नहीं जनता होगा। कुशीनगर सबसे प्रभावित जनपदो में से था। किसान तबाह था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था और न ही किया चीज की सुविधा था। हर जगह माफिया राज था। याद करिए यहां के लोग आज से नौ वर्ष 10 वर्ष पहले किन स्थितियों में रहते थे। यहां पहचान का संकट था। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। आम जनता माफिया और अपराधियों से परेशान था। न स्वास्थ्य की सुविधा थी। न शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। यूपी के अंदर जो सुविधा नहीं थी, यूपी के बाहर जाओ तो पहचान का संकट था।

लॉन्च होते ही ठप हुआ सीबीएसई का री-इवैल्यूएशन पोर्टल, छात्रों को हुई परेशानी; बोर्ड ने दोबारा किया एक्टिव

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (ष्टक्चस्श्व) का पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन पोर्टल लॉन्च होते ही तकनीकी खामियों का शिकार हो गया। करीब चार दिन के इंतजार के बाद पोर्टल के सक्रिय होने से छात्रों को राहत मिली थी, लेकिन कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। हालांकि, बोर्ड का दावा है कि पोर्टल को दोबारा सक्रिय कर दिया गया है।

छात्रों के अनुसार, लॉगिन विवरण दर्ज करने के बाद स्क्रीन फ्रीज हो रही थी, जिससे आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। कई छात्रों ने पोर्टल में आ रही तकनीकी गड़बड़ियों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। वहीं, कुछ छात्रों ने लॉगिन संबंधी समस्याओं की शिकायत दर्ज कराई है।

'रेप पीड़िता को बार-बार कोर्ट न बुलाया जाए', सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, त्रिपुरा हाई कोर्ट का आदेश रद

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेप पीड़िता को ट्रायल के दौरान क्रॉस-एग्जामिनेशन के लिए बार-बार कोर्ट बुलाकर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने त्रिपुरा HC के एक आदेश को रद कर दिया। जिसमें HC ने आरोपी की उस अर्जी को मंजूरी दे दी थी, जिसमें पीड़िता को दोबारा जांच के लिए बुलाने की मांग की गई थी।

जबकि चार साल पहले ही उसका क्रॉस-एग्जामिनेशन हो चुका था। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता पहले ही ट्रायल कोर्ट में चार अलग-अलग मौकों पर गवाही और क्रॉस-एग्जामिनेशन की मुश्किल प्रक्रिया से गुजर चुकी है। इसके अलावा, जांच के दौरान और CrPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने भी उसका बयान दर्ज किया जा चुका है। ऐसे में, क्रॉस-एग्जामिनेशन के चार साल बाद उसे दोबारा बुलाना बहुत ही कठोर कदम होगा। SC ने कहा, 'उसे दोबारा बुलाने का निर्देश देने से पीड़िता को और भी ज्यादा और बेवजह की परेशानी होगी। गवाहों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे बार-बार कोर्ट में पेश होने की परेशानी उठाएं, खासकर संवेदनशील मामलों में। अगर पीड़ितों को, खासकर जघन्य अपराधों के पीड़ितों को, क्रॉस-एग्जामिनेशन के लिए बार-बार कोर्ट में पेश होना पड़े, तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है।' मालूम हो कि HC ने आरोपी की अर्जी पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 311 के तहत पीड़िता को दोबारा बुलाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पाया कि यह अर्जी पीड़िता का क्रॉस-एग्जामिनेशन पूरा होने के चार साल बाद दायर की गई थी, और इतनी लंबी देरी के बाद पीड़िता को दोबारा बुलाने का कोई ठोस आधार मौजूद नहीं था। इसलिए, कोर्ट ने राज्य सरकार की उस अर्जी को मंजूरी दे दी जिसमें HC के आदेश को चुनौती दी गई थी।

'पूरी एक पीढ़ी के साथ विश्वासघात', नीट पेपर लीक को लेकर शशि थरूर ने सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, खासकर नीट-यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बार-बार होने वाली इन गड़बड़ियों को पूरी एक पीढ़ी के साथ विश्वासघात बताया।

थरूर ने कहा, आप ऐसी व्यवस्था चला रहे हैं, जिसमें परीक्षाओं की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जहां छात्र तैयारी में बहुत मेहनत की है, अचानक यह देखते हैं कि पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है और पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई है। कभी-कभी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं और उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है।

उन्होंने भारत की परीक्षा प्रणाली की विश्व स्तर की प्रणालियों से भी तुलना की और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता कहा, दुनिया में कई प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से कराई जाती हैं, चाहे वह एसएटी हो, कैमब्रिज परीक्षाएं हों या आईएससी आदि।

उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों है कि केवल हमारी सरकारी व्यवस्था में ही बार-बार गड़बड़ी हो रही हैं? सरकार ऐसी स्थिति में क्यों है कि वह राष्ट्रीय परीक्षा जैसी सरल प्रक्रिया की निष्पक्षता और ईमानदारी की गारंटी नहीं दे पा रही है? थरूर ने इन लगातार संकटों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, यह वास्तव में सरकार की कमी है और सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए इस समस्या को ठीक करने के लिए कदम उठाने चाहिए। नहीं तो यह पूरी एक पीढ़ी के साथ विश्वासघात है। इसके लिए हम केवल सरकार को ही दोष दे सकते हैं।

'सरकार और एनटीएस जिम्मेदार'

उन्होंने आगे कहा, सरकार, मंत्रालय, एनटीए और वे सभी लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। थरूर ने कहा, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है। यह दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। यह पहली बार नहीं है। लेकिन यह आखिरी बार होना चाहिए।

देश में दो दशकों के सुधार के बाद स्थिर हुई मातृत्व मृत्यु दर की रफ्तार, ताजा आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत मातृत्व मृत्यु दर के लक्ष्य को पाने के बहुत करीब है, लेकिन प्रगति धीमी होने के कारण परिणाम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख पा रहा है। हालांकि, पिछले दो दशकों में MMR में भारी गिरावट आई है, ताजा डेटा दिखाता है कि जो प्रगति पहले बहुत तेजी से हो रही थी। वह अब लगभग रुक गई है और राज्यों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। ताजा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) बुलेटिन के अनुसार, भारत का मातृत्व मृत्यु अनुपात यानी प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या में सिर्फ एक अंक का सुधार हुआ है। यह 2021-23 में 88 से घटकर 2022-24 में 87 हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर आई यह स्थिरता एक बड़े अंतर को छिपाती है, जहां कुछ राज्यों में सुधार हुआ है, वहीं दूसरों की स्थिति बिगड़ी है। इस सुस्ती से पहले, भारत ने 2007-09 में MMR को 212 से घटाकर 2020-22 में 88 कर दिया था, और ऐसा लग रहा था कि वह 2030 तक सतत विकास लक्ष्य (SDG) के 70 के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़, पंजाब और तेलंगाना सहित कई राज्यों ने MMR में 11 से 29 अंकों की कमी की है। बिहार और मध्य प्रदेश, जो दोनों ही उच्च जन्म दर वाले राज्य हैं, उन्होंने भी सुधार किया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने MMR में 10-10 अंकों की कमी की। लेकिन कुछ उच्च प्रजनन दर या अधिक आबादी वाले राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश और झारखंड में, MMR की स्थिति बिगड़ गई।

'भाजपा को पेपर लीक से नहीं, चर्चा से दिक्कत...' अरविंद केजरीवाल का सरकार पर बड़ा हमला

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर तब हमला बोला जब उनके पार्टी नेता ने आरोप लगाया कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने छात्रों के साथ पेपर लीक मामले पर उनकी चर्चा को बाधित किया। संजय सिंह की पोस्ट को साझा करते हुए केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह पेपर लीक जैसी समस्याओं को सुलझाने में कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि इस पर चर्चा को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा को पेपर लीक से कोई समस्या नहीं है। समस्या पेपर लीक पर हो रही चर्चा से है।

यह घटना संजय सिंह द्वारा सोमवार को लगाए गए आरोपों के बाद सामने आई है। संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों से उनकी बातचीत को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि तानाशाही चरम पर पहुंच गई है। X पर वीडियो साझा करते हुए संजय सिंह ने कहा कि प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में तानाशाही चरम पर पहुंच गई है। बंद कमरों में भी लाखों छात्रों के भविष्य पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है; प्रशासन पेपर लीक की बात को भी रोकने के लिए आ गया है। मोदी-योगी की दो इंजन वाली सरकार पूरी तरह विफल हो गई है और विपक्ष को कुचलना चाहती है। वीडियो में संजय सिंह ने व्यवधान को लेकर अधिकारियों से सवाल किया कि क्या देश के लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाले पेपर लीक के बारे में बात करना अवैध हो गया है? उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सार्वजनिक स्थान के लिए अनुमति आवश्यक है। हम कॉन्फ्रेंस रूम में चर्चा कर रहे हैं।

जेट, सेट, गो...114 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में भारत, फ्रांस पहुंचे वायुसेना प्रमुख

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह चार दिन की यात्रा पर फ्रांस गए हैं। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

यह भारतीय वायु सेना के इतिहास में लड़ाकू विमानों की खरीद की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत ने राफेल जेट खरीदने के लिए फ्रांस को एक आधिकारिक प्रस्ताव भेजा है। अब फ्रांस इसकी कीमत, उत्पादन क्षमता और लॉजिस्टिक्स सहायता से जुड़ी विस्तृत जानकारी के साथ जवाब देगा।

इस जवाब के अगले दो से तीन महीनों में आने की उम्मीद है। इसके बाद दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू होगी। अधिकारियों का मानना है कि यह सौदा अगले एक साल के भीतर पक्का हो सकता है।

वायुसेना प्रमुख का ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है?

वायु सेना प्रमुख की इस यात्रा को महज एक औपचारिक दौरा नहीं माना जा रहा है। उम्मीद है कि वे फ्रांस की प्रमुख रक्षा कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इनमें डसॉल्ट एविएशन शामिल है, जो राफेल बनाती है और MBDA शामिल है जो Meteor और SCALP जैसी एडवांस्ड मिसाइलें बनाती है। माना जा रहा है कि ये चर्चाएं सिर्फ विमानों की खरीद तक ही सीमित नहीं रहेंगी। इन बातचीत में भारत में उत्पादन, तकनीकी सहयोग और भारतीय हथियारों को इंटीग्रेट करने जैसे विषय भी शामिल हो सकते हैं।

पीएम मोदी भी कर सकते हैं फ्रांस का दौरा

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के मध्य में फ्रांस का दौरा भी कर सकते हैं। यदि यह दौरा होता है तो राफेल सौदा प्रमुख मुद्दों में से एक हो सकता है। यह सौदा 'सरकार-से-सरकार' मॉडल के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए, दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत को क्यों है विमानों की जरूरत?

भारतीय वायु सेना के लिए 42 स्क्वाड्रन की स्वीकृत संख्या निर्धारित है। लेकिन, वर्तमान में उसके पास केवल 29 स्क्वाड्रन हैं। मिग-21 जैसे पुराने विमानों को सेवा से हटाने के बाद यह कमी और बढ़ गई है। यही कारण है कि 114 नए मल्टीरोल लड़ाकू विमानों की योजना बनाई गई है। इस दौड़ में राफेल को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वायु सेना के पास पहले से ही 36 राफेल जेट मौजूद हैं।

सीजेआई सूर्यकांत 5 नए जजों को दिलाएंगे शपथ, सुप्रीम कोर्ट में 37 हो जाएगी जजों की संख्या

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (2 जून, 2026) को पांच नए जजों का शपथ ग्रहण होगा। कॉलेजियम की सिफारिश को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति ने भी पांचों जजों की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले इन पांच जजों में एक महिला सीनियर एडवोकेट भी शामिल हैं, जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होंगी।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत सुबह 10:30 बजे इन जजों को पद की शपथ दिलाएंगे। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 37 हो जाएगी, जो अब तक की अधिकतम होगी। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमणि मोहना, बंबई हाईकर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर पदोन्नत किया गया है।

पिछले महीने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश सहित 38 करने के लिए एक कानून में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया था। पहले से ही दो रिक्तियां रहने के कारण स्वीकृत संख्या बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुल छह पद रिक्त हो गए थे। हालांकि, आज पांच जजों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज का सिर्फ एक ही पद खाली रह जाएगा।

वरिष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमणि मोहना की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के बाद महिला जजों की संख्या पांच हो जाएगी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी। वी। नागरत्ना इकलौती महिला जज हैं और उनकी नियुक्ति साल 2021 में हुई थी। 2021 के बाद अब किसी महिला जज की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होने जा रही है।

जस्टिस नागरत्ना साल 2027 में रिटायर होंगी और उससे पहले वह एक महीने से ज्यादा समय के लिए सीजेआई का पद भी संभालेंगी यानी वह सीजेआई के पद से सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होंगी। वी। मोहना की उम्र इस समय 59 साल है और वह साल 2031 में रिटायर होंगी। वह बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली दूसरी महिला जज हैं। उनसे पहले जस्टिस इंदु मल्होत्रा ऐसी जज थीं, जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुई थीं। वर्तमान की बात करें तो इस समय सप्रीम कोर्ट में दो और जज हैं, जिनकी बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हुई, जस्टिस पी। एस। नरसिम्हा और जस्टिस के। वी। विश्नवनाथन।

माथे पर तिलक, मन में श्रद्धा: आईपीएल जीतते ही वृंदावन पहुंचे विराट-अनुष्का, प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद

आर्यावर्त संवाददाता

मथुरा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अपनी कप्तानी और बेहतरीन खेल के दम पर आईपीएल 2026 का खिताब जिताने के बाद दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे। आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी जीतने के बाद इस स्टार कपल ने किसी भव्य पार्टी में जाने के बजाय अध्यात्म की राह चुनी। दोनों ने वृंदावन में विख्यात संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया।

यमुना किनारे एकांतवास और आध्यात्मिक चर्चा

विराट और अनुष्का बेहद शांत और निजी तरीके से वृंदावन पहुंचे। दोनों ने यमुना किनारे एकांतवास में समय बिताया। इस दौरान उन्होंने प्रेमानंद महाराज के आश्रम में आयोजित सत्संग में भाग लिया और संत के साथ गहरी आध्यात्मिक चर्चा की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में विराट और अनुष्का बेहद सादगीपूर्ण अंदाज में जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों ने महाराज जी की बातें बेहद ध्यानपूर्वक सुनीं और जीवन व अध्यात्म से जुड़े कई विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रेमानंद महाराज ने भी इस जोड़े को आशीर्वाद देते हुए उन्हें राधा नाम की महिमा और भक्ति का मार्ग समझाया।

वृंदावन से विराट-अनुष्का का पुराना नाता

यह पहली बार नहीं है जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन या किसी आध्यात्मिक यात्रा पर आए हों। इससे पहले भी यह कपल बाबा नीम करोली के आश्रम (कैंची धाम) और वृंदावन के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर हाजिरी लगा चुका है। विराट अक्सर अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर की कृपा और आध्यात्मिक शांति को देते आए हैं। आईपीएल की ऐतिहासिक खिताबी जीत के ठीक बाद भगवान की शरण में पहुंचना उनके इसी विश्वास को दर्शाता है। क्रिकेट के मैदान पर चौके-छक्कों की बरसात करने के बाद, विराट का यह शांत और आध्यात्मिक रूप उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। फैंस सोशल मीडिया पर इस जोड़ी की सादगी और संस्कारों की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

एसडीओ एमपी सिंह के नेतृत्व में जेठ मास के छठे मंगलवार को संपन्न हुआ विशाल भंडारा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। ज्येष्ठ मास के छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर बल्दीराय कस्बे में आस्था, सेवा और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम देखने को मिला। विद्युत विभाग बल्दीराय की ओर से आयोजित विशाल भंडारे में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देर शाम तक चले इस धार्मिक आयोजन में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त किया।

भंडारे से पूर्व विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी (एसडीओ) एम.पी. सिंह के नेतृत्व में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। पाठ के उपरांत श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई। आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। प्रसाद वितरण की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से संचालित की गई, जिससे बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सहभागिता निभाई। एसडीएम प्रवीण कुमार, तहसीलदार अरविंद तिवारी, नायब तहसीलदार गुलाब सिंह तथा एसडीओ एम.पी. सिंह ने स्वयं श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। भंडारे में पूड़ी, सब्जी एवं बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया, जिसे श्रद्धालुओं ने श्रद्धाभाव के साथ ग्रहण किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।

महंगाई, बेरोजगारी व अघोषित बिजली कटौती समेत कई मुद्दों पर सपा ने किया प्रदर्शन

» 30 मई को दूसरे गुट ने भी उन्हीं मुद्दों पर किया था धरना-प्रदर्शन

आर्यावर्त संवाददाता

लंभुआ/सुल्तानपुर। लंभुआ तहसील क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के दो अलग-अलग गुटों द्वारा एक ही मुद्दे को लेकर अलग-अलग तिथियों में प्रदर्शन किए जाने से पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सत्यपाल यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जबकि इससे पहले 30 मई को पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र वर्मा उर्फ बाजीगर वर्मा के नेतृत्व में पार्टी का दूसरा गुट इसी मुद्दे पर प्रदर्शन कर चुका है।

मंगलवार को सुबह से ही लंभुआ स्थित मेला वाली बाग में सपा नेता और कार्यकर्ता जुटने लगे। इसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, पूर्व विधायक संतोष पांडेय तथा अन्य नेताओं के साथ तहसील मुख्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक, महंगाई, बिजली कटौती, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तहसील पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष सत्यपाल यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी प्रीति जैन को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान और सरकार की नीतियों पर पुनर्विचार की मांग की गई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक संतोष पांडेय, पूर्व जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव, जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, जिला सचिव हरकेश यादव, अतेन्द्र जायसवाल सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम से पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं वरिष्ठ नेता परमात्मा यादव, जिला महासचिव सलाउद्दीन सिद्दीकी, जिला उपाध्यक्ष अशोक वर्मा, हाल ही में पार्टी में शामिल हुए श्यामलाल निषाद शगुरुजीश, भजन सिंह यादव तथा हरीश यादव सहित कई प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एक ही मुद्दे पर अलग-अलग गुटों द्वारा पृथक प्रदर्शन किए जाने और वरिष्ठ नेताओं की दूरी से लंभुआ क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की आंतरिक खींचतान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

रेल इंजन में बैठकर बनाई रील, गिरफ्तारी पर बोला– फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया था ऐसा

आर्यावर्त संवाददाता

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर भीतरी रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने रेलवे इंजन की केबिन में घुसकर रील बनाई थी। रील बना रहा युवक वीडियो में शर्टलेस नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद रेल प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

इस मामले में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई। जांच में पता चला कि युवक ने फेमस होने और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के उद्देश्य से बनारस मंडल के सैदपुर भीतरी रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट के केबिन में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रील बनाई थी।

गाजीपुर जनपद के सैदपुर भीतरी रेलवे स्टेशन पर खड़े रेल इंजन के केबिन में घुसकर एक युवक ने रील बनाई थी। सोशल मीडिया पर रील वायरल होने के बाद रेल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर एक आम व्यक्ति इंजन के केबिन तक कैसे पहुंच गया।

मामला रेल प्रशासन के सामने आने पर अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वायरल हो रहे वीडियो में युवक इंजन की नियंत्रण कक्षा तक पहुंचकर रील शूट कर रहा है। रेल इंजन का केबिन एक प्रतिबंधित और संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जहां केवल रेलवे के अधिकृत कर्मचारी ही प्रवेश कर सकते हैं।

वायरल हो रहा वीडियो

इस मामले में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई है। युवक से पूछताछ और जांच में यह पता चला है कि वह फेमस होने और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के उद्देश्य से बनारस मंडल के सैदपुर भीतरी रेलवे स्टेशन पर खड़े रेल इंजन के लोको पायलट के केबिन में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रील बना रहा था।

इसके बाद रेल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवक के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेल अधिकारियों के अनुसार आरोपी युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, इस मामले में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के लिए इस तरह के गैरकानूनी और खतरनाक कार्यों से बचें। उन्होंने कहा कि रेलवे की संपत्तियों और प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश करना कानूनी अपराध है।

22 घंटे तक महुआ के पेड़ तले दबी रही गौमाता, सूचना पर सक्रिय हुए गौरक्षक

» धम्मौर पुलिस ने जेसीबी से हटवाया पेड़,मृत गौमाता को दिलाई गई सम्मान पूर्वक भू-समाधि

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। जिले के धम्मौर थाना क्षेत्र के कर्मचंदपुर गांव में बीते सोमवार को आए तेज आंधी-तूफान के दौरान एक विशालकाय महुआ का पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से एक गौमाता की नीचे दबकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के लगभग 22 घंटे बाद तक मृत गौमाता पेड़ के नीचे दबी रही, जिससे ग्रामीणों में दुःख और आक्रोश का माहौल बना रहा। ग्रामीणों की सूचना पर मंगलवार को राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के जिला संयोजक उदय प्रकाश मिश्रा सक्रिय हुए और पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी देते हुए तत्काल राहत कार्य शुरू कराने की मांग की। उन्होंने जेसीबी मशीन मंगवाकर पेड़ हटाने और मृत गौमाता का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि गौमाता भारतीय संस्कृति, आस्था और सनातन परंपरा का प्रतीक हैं। 22 घंटे तक मृत गौमाता का पेड़ के नीचे दबा रहना बेहद दुःखद और प्रशासनिक संवेदन हीनता को दर्शाता है। प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करते हुए विधिवत भू-समाधि की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं धम्मौर थाना प्रभारी वीपेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से पेड़ की डाल हटवाकर मृत गौमाता को सम्मान पूर्वक भू-समाधि दिलाई गई। इस दौरान थाना प्रभारी वीपेंद कुमार वर्मा, उप-निरीक्षक राज कुमार,आरक्षी संजय यादव समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे।

एक सड़क, 12 घंटे और दो बार भूमिपूजन... रायबरेली में श्रेय लेने की ये कैसी होड़?

आर्यावर्त संवाददाता

रायबरेली। रायबरेली में एक सड़क को लेकर राजनीति गरमा गई है। हैरानी की बात यह है कि महज 12 घंटे के भीतर एक ही सड़क का दो बार भूमिपूजन किया गया। सड़क निर्माण का श्रेय लेने की होड़ में दो जनप्रतिनिधि आमने-सामने नजर आए। हालांकि, इस राजनीतिक खींचतान के बीच सबसे बड़ी राहत स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को मिलने जा रही है, जो वर्षों से जर्जर सड़क की समस्या से जूझ रहे थे। देखिए यह रिपोर्ट।

रायबरेली शहर के आईटीआई मोड़ से सुप्रसिद्ध प्राचीन अभयदाता मंदिर को जोड़ने वाली सड़क लंबे समय से बदहाली का शिकार थी। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण स्थानीय लोगों और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं का आवागमन होता है।

सड़क निर्माण को लेकर उस समय चर्चा तेज हो गई, जब एक ही सड़क का 12 घंटे के भीतर दो बार भूमिपूजन किया गया। पहले सदर विधायक अदिति सिंह ने सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया, वहीं अगले ही दिन नगर पालिका अध्यक्ष शत्रोहन सोनकर ने भी उसी सड़क का भूमिपूजन कर दिया। इसके बाद सड़क निर्माण के श्रेय को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों तक उपेक्षित रही इस सड़क की ओर तब ध्यान गया, जब समाजसेवी विवेक मिश्रा उर्फ पल्लू ने आगे बढ़कर सड़क के गड्ढों में मलबा डलवाया और मार्ग पर रोशनी की व्यवस्था के लिए 15 स्ट्रीट लाइटें लगवाईं। इसके बाद सड़क निर्माण की प्रक्रिया तेज होती दिखाई दी। हालांकि, भूमिपूजन को लेकर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भले ही चर्चा का विषय बनी हुई हो, लेकिन आम जनता का कहना है कि उन्हें राजनीति से ज्यादा सड़क निर्माण से मतलब है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही यह सड़क बनकर तैयार होगी और वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा।

'ठीक है घूंघट करूंगी, मगर ये भी 24 घंटे...', पति तो पति, पत्नी भी निकली जिद्दी, गाजियाबाद के दंपति में अजब–गजब विवाद

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। आधुनिक जीवनशैली, वैचारिक मतभेद और अपनी-अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की जिद ने आज के दौर में वैवाहिक रिश्तों को बेहद नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। गाजियाबाद के परिवार परामर्श केंद्र (फैमिली काउंसलिंग सेंटर) से कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं, जहां महज जींस-टीशर्ट पहनने पर पाबंदी, इंस्टाग्राम रील बनाने की सनक और घूंघट प्रथा के विरोध जैसी वजहों से हंसते-खेलते परिवार बिखर गए। परामर्श केंद्र में आया पहला मामला बेहद अनोखा था, जिसमें एक महिला ने शादी के महज दो दिन बाद ही ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। भोजपुर की रहने वाली सुनीता की शादी एक साल पहले अलवर (राजस्थान) के विनय (दोनों बदले हुए नाम) से हुई थी। सुनीता गृहिणी हैं और विनय एक निजी कंपनी में कार्यरत है। सुनीता का आरोप था कि ससुराल आते ही उस पर जबरन घूंघट करने का भारी मानसिक दबाव बनाया जाने लगा, जो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सीधा हनन है। इस रूढ़िवादी परंपरा का कड़ा विरोध करते हुए विवाहिता ने शर्त रख दी कि "यदि मैं हर वक्त घूंघट में रहूंगी, तो मेरा पति भी दिन-रात शेरवानी पहनकर घूमे।"

काउंसलिंग सेंटर में कई दौर की सुनवाई के बाद भी दोनों पक्ष अपनी जिद पर अड़े रहे और समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार इस अनोखे विवाद की फाइल बंद कर मामला तलाक के लिए कोर्ट भेज दिया गया है।

जींस-टीशर्ट पर पाबंदी और साड़ी का विवाद

एक अन्य मामले में शादी के महज एक हफ्ते बाद ही एक नवविवाहिता परामर्श केंद्र पहुंच गई। उसका आरोप था कि शादी से पहले वो नौकरी करती थी और वेस्टर्न कपड़े पहनती थी, लेकिन ससुराल आते ही उस पर मायके की तरह जींस-टीशर्ट पहनने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। उसे चौबीसों घंटे साड़ी पहनने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उसका पति भी एक निजी कंपनी में काम करता है। हालांकि, इस मामले में काउंसलर्स ने सूझबूझ दिखाई और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर उनके बीच समझौता कराने में सफलता हासिल की।

इंस्टाग्राम रील बनाने की सनक से कलह

तीसरा मामला सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज से जुड़ा हुआ है, जहां एक परेशान पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फैक्ट्री में काम करने वाले पति का आरोप था कि उसकी गृहिणी पत्नी दिनभर इंस्टाग्राम पर रील्स (Short Videos) बनाने में व्यस्त रहती है, जिससे घर की प्राइवेसी और पारिवारिक शांति पूरी तरह भंग हो चुकी है। इतना ही नहीं, वह पूरा दिन मायके में वीडियो कॉल पर व्यस्त रहती है। इस कपल की शादी को तीन साल हो चुके हैं और उनका एक साल का बच्चा भी है। बच्चे के भविष्य को देखते हुए काउंसलर्स ने दोनों को समझाया, जिसके बाद पत्नी ने अपनी आदत सुधारने का वादा किया और मामला शांत हुआ।

लाइफस्टाइल और अनुशासन ने कराया तलाक

वसुंधरा इलाके का एक चौथा मामला पूरी तरह से लाइफस्टाइल और वैचारिक मतभेद से जुड़ा था। यहां एक पढ़ा-लिखा जोड़ा, जिसमें पति और पत्नी दोनों ही आईटी (IT) कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, शादी के महज डेढ़ साल बाद ही अलग होने की कगार पर पहुंच गया। विवाद की वजह बेहद छोटी थी; पति को देर रात तक जागने और सामान को अव्यवस्थित रखने की आदत थी, जबकि पत्नी कड़े अनुशासन और अत्यधिक स्वच्छता की मांग कर रही थी। इस लाइफस्टाइल क्लैश के कारण दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गईं कि उन्होंने काउंसलिंग के बाद भी समझौता करने से मना कर दिया और कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। काउंसलर्स का कहना है कि इन दिनों कपल्स के बीच सहनशीलता की कमी और आधुनिक जीवनशैली के चलते ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

मशहूर सिंगर-एक्टरों के टिकट बुक कराए, अब 10 लाख देने से इनकार! कोचिंग संचालक पर एफआईआर

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक शिक्षण संस्थान के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 'स्कॉलर्स डेन' कोचिंग इंस्टीट्यूट के कर्ता-धर्ता विवेक ठाकुर समेत उनकी दो महिला सहयोगियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। 'मल्होत्रा ट्रैवल्स' के प्रोपराइटर हेमंत मल्होत्रा उर्फ सनी ने मुरादाबाद के मंडलायुक्त आन्जनेय सिंह के समक्ष मामले की शिकायत की थी।

आरोप है कि एक बड़े आयोजन के सिलसिले में ट्रैवल एजेंसी से भारी संख्या में हवाई और अन्य टिकट बुक कराए गए, जिनकी कुल देनदारी 10 लाख रुपये से अधिक की थी। जब पीड़ित व्यवसायी ने इस बकाया राशि

के भुगतान की मांग की थी, तो पैसे देने के बजाय उसे कथित तौर पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी गईं थी। पुलिस ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर इस पूरे मामले में सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

गहनता से जांच में जुटी पुलिस

प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले में गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। शहर के एक जाने-माने शिक्षाविद से जुड़े इस प्रकरण के सामने आने के बाद से स्थानीय व्यावसायिक और प्रशासनिक हल्कों में काफी चर्चाएं हो रही हैं। हेमंत मल्होत्रा ने शिकायत में आरोप लगाया कि पूर्व के व्यापारिक विश्वास के आधार पर उन्होंने जनवरी 2026 में मुरादाबाद में आयोजित होने वाले एक बड़े कार्यक्रम के लिए देश की जानी-मानी हस्तियों के टिकट बुक करने की सहमति दी थी।

हवाई-टैक्सी बुकिंग कराई

इसके बाद संस्था की ओर से रिया और उपासना नामक महिला कर्मचारियों ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से संपर्क कर मशहूर गायकों, अभिनेताओं और निर्देशकों के लिए हवाई सफर और टैक्सी की बुकिंग कराई थी। बार-बार तगादा करने पर भी भुगतान को एकमुश्त देने का झांसा देकर लगातार काम कराया जाता रहा है। कार्यक्रम संपन्न होने तक यह बकाया राशि 10 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर गई थी। लेखाकार के माध्यम से बिलिंग को लेकर भी दबाव बनाया गया। जिससे शिकायतकर्ता का ठगे जाने का एहसास हुआ।

आरोपी ने धमकाया

पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने बकाया धनराशि की मांग को लेकर दबाव बनाया, तो आरोपी पक्ष की ओर से उन्हें डराया-धमकाया गया है। एक अवसर पर जब वे सीधे आरोपी विवेक ठाकुर के कार्यालय पहुंचे थे, तो वहां भी उन्हें साफ शब्दों में पैसे देने से मना कर दिया गया और 'जो करना है कर लो' जैसी चेतावनी दी गई। आखिर में न्याय न मिलने पर पीड़ित ने कमिश्नर के समक्ष गुहार लगाई थी। जिसके बाद थाना सिविल लाइंस में केस दर्ज किया गया है। वर्तमान में पुलिस इस आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के मामले की बारीकी से तफ्तीश कर रही है।

वरासत के नाम पर रिश्वत लेना पड़ा महंगा, गिरफ्तार

सुल्तानपुर। जिले के जयसिंहपुर तहसील में तैनात लेखपाल को वरासत के नाम पर रिश्वत लेना महंगा पड़ गया।किसान की शिकायत पर पहुंची अयोध्या एंटी करेप्शन की टीम ने उन्हें रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

मामला जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के पीढ़ी चौराहे से जुड़ा है।जहां शिकायत कर्ता की शिकायत पर जाल बिछाकर पहुंची एंटी करेप्शन टीम ने वरासत के नाम पर पीढ़ी गांव में तैनात लेखपाल विवेक वर्मा को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तारी के बाद एंटी करेप्शन टीम आरोपी लेखपाल को लेकर कूरेभार थाने पहुंची। जहां एंटी करेप्शन टीम की तरफ से मुकदमा दर्ज किया।आरोपी लेखपाल जयसिंहपुर क्षेत्र के अलावलपुर गांव का निवासी है।एंटी करेप्शन थाना अयोध्या के प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को कूरेभार थाने में रखा गया है।जो किसान से वरासत के नाम पर 05 हजार रुपए रिश्वत लिया था।

बड़े मंगल पर भंडारों में पहुंचीं महापौर, श्रद्धालुओं को वितरित किया प्रसाद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। ज्येष्ठ मास के पावन बड़े मंगल के अवसर पर राजधानी लखनऊ में आयोजित विभिन्न धार्मिक एवं सेवा कार्यक्रमों में महापौर सुषमा खर्कवाल शामिल हुईं। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर आयोजित भंडारों में पहुंचकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया तथा नगरवासियों के सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की।महापौर ने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के निकट आयोजित विशाल भंडारे से की, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण में सहभागिता की। इसके बाद वह घंटाघर चौराहे के निकट अभियंत्रण जोन-6 कार्यालय परिसर में आयोजित भंडारे में पहुंचीं और वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से मुलाकात कर सेवा कार्यों में भाग लिया।इस अवसर पर महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि बड़ा मंगल लखनऊ की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है, जो सेवा, समर्पण, परोपकार और सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि बड़े मंगल पर आयोजित भंडारे समाज में एकता, सहयोग और मानव सेवा की भावना को मजबूत करते हैं तथा लोगों को एक-दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं।महापौर ने पवनपुत्र हनुमान के चरणों में प्रदेश और नगर की खुशहाली की प्रार्थना करते हुए कहा कि यह पर्व लोककल्याण और जनसेवा की भावना को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने सभी नगरवासियों को बड़े मंगल की शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।बड़े मंगल के अवसर पर आयोजित इन धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भंडारों में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया तथा पूरे दिन भक्ति और सेवा का वातावरण बना रहा। कार्यक्रमों में अनेक गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे।

बड़े मंगल पर सपा मुख्यालय और सदर में हुआ पूजन व भंडारा, राजेंद्र चौधरी ने वितरित किया प्रसाद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। ज्येष्ठ मास के पांचवें बड़े मंगलवार के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय सहित राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक आयोजन और भंडारों का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने वीरवर हनुमान जी की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की तथा श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया।समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में बड़े मंगलवार के अवसर पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष विशेष पूजा-अर्चना की गई। इस अवसर पर राजेंद्र चौधरी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धाभाव से पूजन किया और उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित किया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।इसके बाद राजधानी के विधानसभा कैंट क्षेत्र स्थित सदर में प्रभू दयाल सेठ रोड पर सेठ परिवार द्वारा आयोजित पारंपरिक भंडारे में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पांचवें बड़े मंगल के अवसर पर आयोजित इस भंडारे में राजेंद्र चौधरी ने हनुमान जी के पूजन के उपरांत श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया।भंडारे में पूड़ी-सब्जी, कढ़ी-चावल, बूंदी, हलुआ, शिकंजी और आइसक्रीम का वितरण किया गया। दोपहर से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं और लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धार्मिक आयोजन में सहभागिता निभाई।इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विशेष कार्याधिकारी आशीष यादव सोनू, वरिष्ठ पत्रकार मधुकर त्रिवेदी तथा सेठ परिवार के सदस्य मनोज सेठ, अजय सेठ, विशाल सेठ, दिलीप सेठ, रवि सेठ, अर्श, सौरभ, अभय, अतुल, अंजू, अमीशा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे।कार्यक्रम में रविन्द्र अरोरा, मनप्रीत सिंह, कमल सिंह, देवेन्द्र सिंह, विनायक मेहरा, मुकुल टंडन, सोमेश टंडन, जाहिद, पुत्तू, विशाल, विकास, रूचि, संजय खान और अनीश गर्ग सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया।

पोषणयुक्त भोजन से बच्चों का हो रहा सर्वांगीण विकास

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ-साथ उत्तम स्वास्थ्य और पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री पोषण योजना के माध्यम से राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठ तक के लाखों छात्र-छात्राओं को प्रतिदिन संतुलित, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को मजबूती मिल रही है तथा कुपोषण के खिलाफ चल रहे अभियान को भी नई गति प्राप्त हुई है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री पोषण योजना केवल विद्यालयों में भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है।

दो महीने से वेतन नहीं मिलने पर पीसीएस अधिकारियों में नाराजगी, प्रोन्नत पीसीएस संघ ने शासन से किया हस्तक्षेप का अनुरोध

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैनात अनेक प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों को पिछले दो महीनों से वेतन न मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पीसीएस (प्रोन्नत) अधिकारी संघ ने शासन को पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संघ का कहना है कि नियुक्ति अनुभाग-11 द्वारा समय से वेतन पर्चियां जारी न किए जाने के कारण अप्रैल और मई माह का वेतन आहरित नहीं हो सका है, जिससे अधिकारियों को आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।संघ के अध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को भेजे पत्र में कहा है कि प्रदेश के कई जनपदों में कार्यरत पीसीएस अधिकारियों को लगातार दो माह से वेतन नहीं मिला है। संघ के संज्ञान में आए मामलों के अनुसार वेतन भुगतान में देरी का मुख्य कारण नियुक्ति अनुभाग-11 द्वारा संबंधित अधिकारियों की वेतन पर्चियां समय पर जारी न किया जाना है। वेतन पर्ची के अभाव में कोषागार से वेतन का आहरण संभव नहीं हो पा रहा है।संघ ने अपने पत्र में कहा है कि लगातार दो महीने तक वेतन न मिलने से अधिकारियों को अपने पारिवारिक खर्चों के संचालन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की शिक्षा, गृह ऋण और अन्य ऋणों की मासिक किश्तों के भुगतान, चिकित्सा व्यय तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभावित हो रही है। इससे अधिकारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ने के साथ-साथ मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो रहा है।पत्र में यह भी कहा गया है कि संबंधित अधिकारी फील्ड और सचिवालय स्तर पर पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में केवल तकनीकी अथवा प्रक्रियागत कारणों से वेतन का रुक जाना उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। संघ का मानना है कि नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया होने के बावजूद वेतन पर्चियां जारी करने में हो रही देरी चिंताजनक है।संघ ने शासन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया है कि अभी तक वेतन पर्चियों के निर्गमन में हो रहे विलंब का कोई स्पष्ट और ठोस कारण सामने नहीं आया है। जबकि यह प्रक्रिया प्रत्येक माह नियमित रूप से पूरी की जाती है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों को बिना किसी गलती के वेतन से वंचित रहना पड़ रहा है।उत्तर प्रदेश पीसीएस (प्रोन्नत) अधिकारी संघ ने प्रमुख सचिव से अनुरोध किया है कि मामले का तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ताकि लंबित वेतन पर्चियां युद्धस्तर पर जारी की जा सकें और प्रभावित अधिकारियों का अप्रैल एवं मई माह का वेतन शीघ्र भुगतान हो सके।संघ के अनुसार सीतापुर, बलिया, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, मैनपुरी, देवरिया, मथुरा, बुलंदशहर, अमरोहा, महाराजगंज, संत कबीर नगर और लखनऊ सहित कई जनपदों के अधिकारी इस समस्या से प्रभावित हैं। दो महीने से वेतन न मिलने के कारण इन अधिकारियों में असंतोष बढ़ रहा है।संघ ने उम्मीद जताई है कि शासन इस गंभीर विषय पर शीघ्र निर्णय लेकर लंबित वेतन भुगतान का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रशासनिक हलकों में भी इस मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के वेतन भुगतान में इतनी लंबी देरी असामान्य मानी जा रही है।

महिला सशक्तिकरण की मिसाल बना कानपुर देहात

लखनऊ। महिलाओं और बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक उत्थान को प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जनपद कानपुर देहात में प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही हैं। महिला कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बड़ी संख्या में महिलाओं और बालिकाओं को इन योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।जनपद में संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए सहारा बनकर उभरी है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 35 हजार 945 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। नियमित आर्थिक सहायता मिलने से विधवा, परित्यक्ता और जरूरतमंद महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिला है।

यूपीपीसीएल के पेंशनरों को तोहफा, महंगाई राहत बढ़कर 60 प्रतिशत हुई

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) एवं उसकी सहयोगी विद्युत वितरण कंपनियों के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ मिलेगा। कॉरपोरेशन ने 1 जनवरी 2026 से पुनरीक्षित पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत स्वीकृत कर दी है। इसके साथ ही महंगाई राहत की कुल दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है।यूपीपीसीएल के निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा 21 मई 2026 को जारी शासनादेश के अनुरूप लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत प्रदान करने की स्वीकृति दी थी, जिसके क्रम में पावर कॉरपोरेशन एवं उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों तथा केस्को के पेंशनरों को भी समान लाभ दिया गया है।आदेश के अनुसार बढ़ी हुई महंगाई राहत 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और पुनरीक्षित पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन पर 60 प्रतिशत की दर से देय होगी। यह सुविधा 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों पर भी लागू होगी।कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि महंगाई राहत की गणना में एक रुपये के आधे से कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा, जबकि आधा या उससे अधिक राशि को पूर्ण रुपये माना जाएगा। साथ ही अतिरिक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिए किसी अलग प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी तथा राजकीय कोषागार सीधे इस आदेश के आधार पर भुगतान कर सकेंगे।यूपीपीसीएल ने सभी वितरण कंपनियों, कोषागार अधिकारियों और संबंधित लेखा अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

○ संक्षेप ○

प्रताप सिंह बघेल ने संभाला माध्यमिक शिक्षा निदेशक का कार्यभार

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग के नवनियुक्त प्रभारी निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने मंगलवार को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक कर विभाग की कार्यप्रणाली, योजनाओं और प्राथमिकताओं की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर अधिकारियों ने उनका स्वागत करते हुए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं तथा वर्तमान गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोजित बैठक में प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तथा रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने, शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने तथा शिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को समन्वित प्रयास करने होंगे।उन्होंने कहा कि विद्यालयों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

हरित उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते कदम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण, वन संवर्धन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए लगातार व्यापक और नवाचारी प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में वृक्षारोपण, आर्द्र भूमि संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और आधुनिक तकनीकों के उपयोग के माध्यम से हरित क्षेत्र के विस्तार पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष प्रदेश में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। विभागीय पौधशालाओं में वर्तमान समय में 52 करोड़ 46 लाख से अधिक पौधे उपलब्ध हैं।प्रदेश सरकार का मानना है कि वृक्षारोपण अभियान की सफलता में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से किसानों को वृक्षारोपण से होने वाले आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही कार्बन वित्तपोषण के माध्यम से आय बढ़ाने की संभावनाओं से भी उन्हें अवगत कराया जा रहा है।

नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने का आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के तहत अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नाका हिंडोला पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस ने नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के पास से पकड़ा गया, जिसके बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।पुलिस के अनुसार 1 जून 2026 को पीड़िता के पिता ने थाना नाका हिंडोला में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को एक युवक शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया है। शिकायत के आधार पर थाना नाका हिंडोला में मुकदमा अपराध संख्या 89/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) और 87 में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के निर्देशन और सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग के पर्यवेक्षण में विशेष पुलिस टीम गठित की गई।

बर्थडे पार्टी की बुकिंग बनी साजिश, फोटोग्राफर को बुलाकर लाखों के कैमरे और उपकरण लूटे

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी के इटौंजा क्षेत्र में अपराधियों ने एक फोटोग्राफर को जन्मदिन समारोह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का झांसा देकर सुनियोजित तरीके से लूट का शिकार बना दिया। बदमाशों ने पहले कार्यक्रम की बुकिंग के नाम पर संपर्क किया, फिर सुनसान स्थान पर बुलाकर उसकी कार रोक ली और लाखों रुपये मूल्य के कैमरे, लेंस, गिम्बल तथा मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दावा किया है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है।पुलिस के अनुसार ग्राम रानीखेड़ा, थाना माल निवासी अशोक यादव, जो पेशे से फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर हैं, ने मंगलवार को थाना इटौंजा पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनसे संपर्क कर जन्मदिन समारोह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने की बात कही थी। कार्यक्रम के लिए उन्हें 1 जून की रात लगभग साढ़े आठ बजे नीलांश वाटर पार्क रोड के पास बुलाया गया।अशोक यादव के अनुसार जब वह अपने उपकरणों के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार युवकों ने उनकी कार को घेर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने उन्हें धमकाया और उनके पास मौजूद महंगे फोटोग्राफी उपकरण अपने कब्जे में ले लिए। वारदात के दौरान विरोध करने पर उन्हें भयभीत किया गया, जिसके बाद आरोपी आराम से सामान लेकर मौके से फरार हो गए।

दहेज हत्या के मामले में वांछित पति गिरफ्तार, ट्रॉमा सेंटर से दबोचा गया आरोपी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सआदतगंज पुलिस ने दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपनी पत्नी की कथित दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहा था और ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी मिलने के बाद शहर छोड़कर भागने की फिराक में था।पुलिस के अनुसार सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला और प्रभारी निरीक्षक सआदतगंज के निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर ट्रॉमा सेंटर, केजीएमयू से सागर लोधी (29) निवासी सुल्तानपुर गढ़ैया, थाना सआदतगंज को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ थाना सआदतगंज में मुकदमा अपराध संख्या 111/2026 के तहत धारा 80(2), 85 बीएनएस तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 में मामला दर्ज है।पुलिस के मुताबिक 31 मई 2026 को कानपुर निवासी सुनील कुमार वर्मा ने थाना सआदतगंज में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी 23 वर्षीय भतीजी को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। शिकायत के आधार पर मृतका के पति सागर लोधी तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद से सागर फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही थी।मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ट्रॉमा सेंटर में उपचार करा रहा है और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद फरार होने की योजना बना रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने ट्रॉमा सेंटर यूनिट-1 के पास घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने अपनी पहचान सागर लोधी पुत्र राजेश लोधी के रूप में बताई।पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह दहेज हत्या के मुकदमे में नामजद होने के कारण गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है और मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच जारी है।गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक विशाल कुमार यादव, उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार वर्मा, उपनिरीक्षक विशाल पटेल, कांस्टेबल अंकित कुमार, कांस्टेबल बृजेश कुमार तथा कांस्टेबल अवनीश कुमार शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

एनटीपीसी बकाया और पुराने देयों को सरचार्ज में शामिल करने पर जताई आपत्ति

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। जून माह में बिजली उपभोक्ताओं पर लगाए गए फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) को लेकर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने प्रथम दृष्टया यह माना है कि एनटीपीसी को देय बकाया राशि, न्यायिक आदेशों के अनुपालन में किए गए भुगतान तथा पूर्व वर्षों के लंबित देयों को एफपीपीएएस की गणना में शामिल करना नियामकीय प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।आयोग के सचिव सुमीत कुमार अग्रवाल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि यूपीपीसीएल की ओर से जून 2026 के लिए एफपीपीएएस 20.61 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ विनियम) विनियम, 2025 के प्रावधानों के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा के कारण जून माह में उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत एफपीपीएएस ही वसूला जाना प्रस्तावित है।आयोग ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि उसे यूपीपीसीएल की नियामकीय मामलों की इकाई की ओर से 29 मई 2026 को भेजे गए पत्र के साथ-साथ विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों की भी जानकारी मिली है। इन रिपोर्टों में कहा गया था कि बिजली खरीद लागत में हुई असाधारण वृद्धि का मुख्य कारण अपीलीय विद्युत अधिकरण (एपीटीईएल) के आदेशों के अनुपालन में एनटीपीसी को किए गए बकाया भुगतान तथा केंद्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) के पुराने लंबित देयों का निस्तारण है।आयोग ने स्पष्ट किया है कि एफपीपीएएस का उद्देश्य केवल ईंधन लागत, बिजली खरीद लागत और पारेषण शुल्क में होने वाले वास्तविक मासिक उतार-चढ़ाव का समायोजन करना है। विनियम 16.1(3) के अनुसार किसी भी माह का एफपीपीएएस उस माह में खरीदी गई और उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई बिजली की वास्तविक लागत में हुए बदलाव के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे में पूर्व वर्षों की देनदारियों, ऐतिहासिक बकायों, एकमुश्त समझौतों अथवा पुराने दावों की वसूली एफपीपीएएस के माध्यम से नहीं की जा सकती।आयोग ने कहा है कि इस प्रकार की देनदारियां टू-अप प्रक्रिया के अंतर्गत विचारणीय होती हैं, जहां आयोग संबंधित खर्चों की वैधता, औचित्य, उपभोक्ता हितों पर प्रभाव तथा उनकी वसूली की अनुमति का परीक्षण करता है।

बड़े मंगल पर अजय राय ने किए हनुमान जी के दर्शन, सुंदरकांड पाठ और भंडारों में किया सहभाग

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने राजधानी के विभिन्न स्थानों पर आयोजित सुंदरकांड पाठ और भंडारों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने हजरतगंज स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और उन्नति की कामना की। साथ ही श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया। अजय राय ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत आलमबाग क्षेत्र के चंदर नगर गेट के निकट स्थित मौनी बाबा मंदिर से की। यहां आयोजित सुंदरकांड पाठ और भंडारे में शामिल होकर उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान में सहभाग किया तथा उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। बड़े मंगल के अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मौजूद रही।इसके बाद वह हजरतगंज चौराहे पर स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत दर्शन-पूजन किया और प्रदेश की खुशहाली, शांति तथा जनकल्याण की प्रार्थना की। बड़े मंगल के अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा।तत्पश्चात अजय राय हजरतगंज स्थित जनपथ बाजार पहुंचे, जहां कांग्रेस कमेटी के प्रोटोकॉल प्रभारी रमेश मिश्रा द्वारा आयोजित विशाल भंडारे में उन्होंने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ प्रसाद ग्रहण किया और स्वयं भी प्रसाद वितरण कर सेवा कार्य में सहभागिता निभाई।इस अवसर पर अजय राय ने कहा कि ज्येष्ठ माह में बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा-अर्चना और भंडारे की परंपरा वर्षों से चली आ रही है।

मियावकी वन तकनीक से हरित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते कदम

वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए मियावाकी तकनीक एक बेहद प्रभावी और लोकप्रिय विधि बन गई है। जापानी वनस्पतिशास्त्री डॉ. अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित यह तकनीक केवल 2-3 वर्षों में बंजर भूमि को घने, आत्मनिर्भर सूक्ष्म वनों में बदल देती है। पारंपरिक वृक्षारोपण की तुलना में यह विधि 10 गुना तेजी से बढ़ती है और 30 गुना अधिक घने जंगल बनाती है, जो शहरी क्षेत्रों के लिए आदर्श है। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए मियावकी वन तकनीक तेजी से अपनाई जा रही है। राज्य में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस तकनीक के जरिए शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और खनन प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर हरियाली विकसित की जा रही है। मियावकी पद्धति में स्थानीय प्रजातियों के पौधों को अधिक घनत्व में लगाया जाता है, जिससे मात्र 3 से 5 वर्षों में घना जंगल तैयार हो जाता है।

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 से मियावकी पद्धति के तहत लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। वर्ष 2022 में कोटा मण्डल में एनटीपीसी लिमिटेड के सहयोग से 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 23 हजार पौधे तथा 0.3 हेक्टेयर में 7 हजार पौधे लगाए गए। वर्ष 2023 में कोटा के भिल्मी क्षेत्र में 6.4 हेक्टेयर भूमि पर 64 हजार पौधों का रोपण किया गया। वहीं गेवरा क्षेत्र में 2 हेक्टेयर भूमि पर 20 हजार पौधे लगाए गए। वर्ष 2024 में कोटा के उच्चभट्ठी क्षेत्र में 3.2 हेक्टेयर में 32 हजार पौधे लगाए गए। इसके अलावा रायगढ़ मण्डल के तिलईपाली और छाल क्षेत्रों में कुल 3.75 हेक्टेयर भूमि पर 37 हजार 500 पौधों का सफल रोपण किया गया।

वर्तमान में राज्य के कई क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य तेजी से जारी है। बारनवापारा मण्डल में 'हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत 6 हजार पौधे लगाए जा रहे हैं। कोरबा और रायगढ़ क्षेत्रों में साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सहयोग से 4 हेक्टेयर क्षेत्र में 40 हजार पौधों का रोपण किया जा रहा है। वहीं विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत महानदीकोलफील्ड लिमिटेड द्वारा 1.9 हेक्टेयर भूमि पर 64 हजार पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अरपा नदी के किनारे भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर हरित क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार मियावकी वन सामान्य जंगलों की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। यह तकनीक वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने, भू-जल स्तर सुधारने और मिट्टी संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन वनों की शुरुआती वर्षों में देखभाल की जाती है, जिसके बाद ये जंगल स्वतः विकसित होने लगते हैं। इससे रखरखाव की लागत कम होती है और लंबे समय तक पर्यावरणीय लाभ मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल करते हुए कोरबा जिले के गेवरा क्षेत्र के 12.45 हेक्टेयर डंप क्षेत्र में 33 हजार 935 मिश्रित प्रजातियों के पौधों का सफल रोपण किया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।

कोयला खनन के बाद डंप क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी नीचे दब जाती है और ऊपर पत्थर, कोयला अवशेष तथा अनुपजाऊ मिट्टी रह जाती है। ऐसे क्षेत्रों में पौधों का उगना बेहद कठिन माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति और सतत प्रयासों से इस बंजर भूमि को अब हरियाली में बदला जा रहा है। डंप क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए वर्मी कम्पोस्ट, नीमखली और डीएपी का उपयोग किया गया। जीपीएस सर्वे और सीमांकन के बाद व्यवस्थित गड्ढे तैयार किए गए तथा 3 से 4 फीट ऊंचाई वाले स्वस्थ पौधों का रोपण किया गया। इस क्षेत्र में नीम, शीशम, सिरस, कचनार, करंज, आंवला, बांस, महोगनी, महुआ और बेल जैसी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इससे आने वाले समय में यह क्षेत्र पक्षियों और अन्य वन्य जीवों के लिए भी उपयुक्त आवास बन सकेगा।

शुरुआती 2-3 वर्षों की देखभाल के बाद, यह वन पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है और इसे किसी उर्वरक या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। रोपण के बाद पौधों की नियमित सिंचाई, खाद, निंदाई-गुड़ाई, घास कटाई और सुरक्षा का कार्य लगातार किया जा रहा है। मृत पौधों का समय पर प्रतिस्थापन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्ष 2025 से 2029 तक पांच वर्षों तक रखरखाव के बाद इस विकसित हरित क्षेत्र को साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड गेवरा को सौंपा जाएगा। कम जगह में घने जंगल बनाकर शहरों में प्रदूषण (धूल और ध्वनि) को कम करने में सहायक होते हैं। ये वन पारंपरिक वनों की तुलना में 30 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। गेवरा की यह पहल दर्शाती है कि सही योजना, वैज्ञानिक तकनीक और निरंतर प्रयासों से बंजर और पत्थरीली भूमि को भी घने जंगल में बदला जा सकता है।

ओ पी की विकासपरक राजनीति बनाम सिंदूर पार्क ऑक्सीजोन

विकास अपने-आप में एक विस्तृत व बहुआयामी अवधारणा है। ओ पी चौधरी के लिये विकास का आशय केवल बड़े व मेगा प्रोजेक्ट्स को मूर्तरूप देने तक सीमित नहीं है

मुकेश जैन

किसी शहर का सर्वांगीण विकास एक जटिल और श्रम-साध्य मसला है, विशेषकर किसी पुराने बसाहट वाले शहर का व्यवस्थित विकास बहुत ही पेचीदा होता है। इसके लिये शहरवासियों की जरूरतों की ठीक-ठीक समझ, वहाँ की पारिस्थितिक विशेषताओं, सांस्कृतिक परिवेश, परंपराओं व विरासत के साथ संतुलन स्थापित करना , इसके ठीक समानांतर आधुनिक भविष्य की जरूरतों के साथ भी तालमेल कायम रख पाना और इन सबके बीच ठोस व समयबद्ध कार्ययोजना का निर्माण तथा योजनाओं को धरातल पर उतारने का आवेगपूर्ण संकल्प, सभी का एकजायी होना आवश्यक होता है। यह सुखद संयोग है कि रायगढ़वासियों को इन सभी विशिष्ट योग्यताओं से परिपूर्ण ओ पी चौधरी का कुशल नेतृत्व मिला है और इस अंचल से दिली-लगाव रखने वाले विष्णु देव साय मुख्यमंत्री के रूप में हमारे साथ हैं। कहते हैं कि जब नेतृत्व सबल, नियत साफ और सोच बड़ी हो तो जनता के सपनों को न केवल पंख लग जाते हैं वरन एक-एक करके सपने साकार भी होने लगते हैं। रायगढ़ में विगत ढाई वर्षों से चल रहे विकास कार्यों की लंबी श्रृंखला इसकी बानगी है। इस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में शहर के हृदय स्थल में नवनिर्मित बेहतरीन ऑक्सीजोन कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के करकमलों से आमजनता को अर्पित हुआ है। निश्चित रूप से यह अवसर रायगढ़ के नव-विकास के शिल्पी ओ पी चौधरी की पीठ थपथपाने और हमारे लाड़ले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करने का क्षण है। यह रायगढ़ के चेहरे पर एक मीठी व लम्बी मुस्कान बिखरने का क्षण है।

अतीत की उपेक्षा और नया संकल्प- जब हम रायगढ़ के अतीत पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि मध्यप्रदेश के धूर-पूर्वी छोर का अंतिम शहर होने के कारण हमारा रायगढ़ दशकों तक भोपाल में बैठे नीति-निर्धारकों की दृष्टि से लगभग ओझल ही रहा। रायगढ़ को 1901 में नगरपालिका परिषद का दर्जा मिला। तब से लेकर 2001 तक 100 वर्षों के लंबे कालखण्ड में रायगढ़ बेहद मंथर गति से यात्रा करता रहा। मध्यप्रदेश के बड़े शहरों की ओट में दुबक कर रायगढ़ यथास्थिति में रहने का अभिशाप झेलता रहा। हमारे आस-पास के रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग भी विकास के मामले में हमसे काफी आगे निकल गये। अटल जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दिये जाने के बाद परिस्थितियां बदली। 2002 में रायगढ़ को निगम का दर्जा हासिल हुआ। 2003 में नये नेतृत्व को काम करने का मौका मिला और रायगढ़ उपेक्षा के दौर से बाहर निकलकर विकास की दहलीज छूने लगा। इस दौर में कतिपय उल्लेखनीय काम जरूर हुये लेकिन 100 वर्षों के बैकलॉग के सामने ये नाकाफी थे। चूंकि लंबे समय की जड़ता थी इसलिये विकास की मुख्यधारा में लाने के लिये फुटकर प्रयासों से काम नहीं चलने वाला था। उसे एकमुश्त बड़ी छलांग लगाने की जरूरत थी और इस सिद्धि के लिये रायगढ़ किसी ताकतवर एवं सक्षम उद्धारक की बांट जोह रहा था। उनकी वर्षों की यह तलाश ओ पी चौधरी तक आकर पूर्ण हुई है। रायगढ़ के वृहत काया-कल्प हेतु चल रहे सौ से अधिक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स और उन पर ताबड़-तोड़ एक्शन इस बात के जीवंत प्रमाण हैं। विगत दो-ढाई वर्षों के अनथक क्रियाकलापों से ओ पी ने 'एक ही राजनीति- विकास की राजनीति' के मूलमंत्र को कार्य रूप में सिद्ध करके दिखाया है।

विकास अपने-आप में एक विस्तृत व बहुआयामी अवधारणा है। ओ पी चौधरी के लिये विकास का आशय केवल बड़े व मेगा प्रोजेक्ट्स को मूर्तरूप देने तक सीमित नहीं है वरन आम लोगों के आर्थिक व सामाजिक जीवन का उत्थान व जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव उनके लिये विकास का असली पैमाना है। विकास कार्यों की लंबी श्रृंखला- नालन्दा परिसर, केलो-नहर निर्माण, प्रस्तावित रिंग रोड, मेरीन ड्राइव, स्टेडियम का उन्नयन, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, प्रयास विद्यालय, आधुनिक बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन का आधुनिकीकरण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, सीवरेज, सड़क, पुल-पुलियों के साथ ही पहाड़ मंदिर का ईको-सेंटर की तर्ज पर विकास , उर्दना में नगर -वन की स्थापना और शहर के चारों ओर अलग-अलग ऑक्सीजोन का निर्माण यह दर्शाता है कि ओ पी चौधरी लोगों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण बदलाव को लेकर कितने संजीदा हैं। बहुपयोगी सुविधाओं से लैस ऑक्सीजोन - शहर के बीचों-बीच इतवारी बाजार और कृषि-उपज मंडी का बड़ा भूखंड लगभग अनुपयोगी सा पड़ा था। इस पर कभी मल्टीस्टोरी शापिंग काम्प्लेक्स व मल्टी लेबल आधुनिक पार्किंग की योजना बनी और कभी ऑडिटोरियम निर्माण की योजना बनी लेकिन विभिन्न विभागों में सामंजस्य की कमी और राजनीतिक अड़ंगेबाजी के कारण कोई भी योजना परवान नहीं चढ़ सकी। इस बेशकीमती भूखंड का व्यावसायिक उपयोग करके शासन इसे बड़े आर्थिक रिटर्न व एक नियमित आय का जरिया बना सकती थी लेकिन ओ पी चौधरी ने इसे आम जनता के हितार्थ ऑक्सीजोन के लिये चुना और इसके बहुपयोगी स्वरूप की परिकल्पना की तो उसके पीछे गहरी सोच व गूढ़ निहितार्थ हैं। शहर के आस-पास उद्योगों की स्थापना, शहर के भीतर वृहत कांक्रीटीकरण और बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही आदि कारणों से शहर में कार्बनडाइऑक्साइडका स्तर अपेक्षाकृत अधिक होता है। अलग-अलग स्थानों में ऑक्सीजोन के निर्माण के द्वारा ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना आम तौर पर पर्यावरणीय संतुलन कायम करने का एक समाधानकारक व बेहतर विकल्प होता है। नवनिर्मित ऑक्सीजोन में विशेषज्ञों की सलाह पर अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाले पेड़-पौधे लगाये गये हैं, बच्चों के मनोरंजन हेतु झूले-फिसलपट्टी आदि की व्यवस्था है, योग हेतु अलग मंच, ओपन एयर थिएटर सहित वॉकिंग ट्रैक भी है। इससे लगकर एक गेम-जोन व फ़ूडकोर्ट और व्यवस्थित पार्किंग का निर्माण भी किया गया है। संक्षेप में, जहां एक ओर यह ऑक्सीजोन काफी हद तक प्रदूषण से राहत देने वाला केंद्र होगा वहीं दूसरी ओर यह सैर-सपाटे, योग, स्वच्छ हरित पट्टिका, वॉकिंग, कला मंचन आदि की सुविधाओं से लैस उपयोगी स्वास्थ्य केंद्र , कम्युनिटी मीटिंग और कलात्मक व सांस्कृतिक मेल-जोल के केंद्र के रूप में भी उपयोगी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री साय की मंशा के अनुरूप हुआ नामकरण - इस ऑक्सिजोन के साथ एक विशिष्ट और उल्लेखनीय विषय इसके नाम का चयन भी है। विदित हो कि पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा काश्मीर घाटी में भारतीय महिलाओं के सामने ही उनका सिंदूर मिटा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसी नेतृत्व में भारतीय सेना ने अद्भूत शौर्य का प्रदर्शन करते हुये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान को ऐसा मुँह-तोड़ जवाब दिया था कि पूरा विश्व अचंभित हो गया।

टिप्पणी

देश की मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक, प्रतिभा पर गिद्धों का डेरा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नीट परीक्षा (नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट) का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द करदी गई है।यह नीट परीक्षा देश भर के 22 लाख परीक्षार्थियों ने 3 मई को देश भर के 1500 से अधिक केंद्रों पर दी थी।इस मामले से यह साबित हो गया है कि देश में प्रतिभा पर गिद्धों का डेरा है।अबकी बार इन गिद्धों रूपी मांगीलाल और दिनेश रीयल सेक्टर के जयपुर के कारोबार से जुड़े ने नासिक एक बेहद प्रतिष्ठित प्रेस से पूरा पेपर 30 लाख में खरीदा और उसे सबसे पहले अपने पुत्र को सीकर में उपलब्ध करवाया। उसके बाद जयपुर से महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना,में विभिन्न ठिकानों पर लाखों रुपए में बेच कर लगभग 10 करोड़ रुपए वसूल किए।

ये पेपर 26,27 अप्रैल को खरीदा गया। चुकी सॉफ्ट कॉपी में था इसलिए एक दिन में ही पूरे भारत में सर्कुलेट हो गया था।

सबसे पहले जयपुर में पुलिस को एक गैस पेपर मिला जो 420 प्रश्न का था उसमें केमिस्ट्री के 120 प्रश्न हू ब हु ओरिजनल पेपर में थे ।एक कोचिंग यह जारी किया था तब पुलिस का माथा ठनका तो मालूम हुआ कि पूरा पेपर ही कई विद्यार्थी पर था ।इस पर केंद्रीय मंत्री शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान ने संज्ञान लिया और जांच कराई तो पाया कि पूरे देश में व्हाट्सएप के जरिए फेल गया ।कई लोगों ने पच्चीस हजार में खरीदा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीबीआई की रिपोर्ट पर परीक्षा रद्द कर दी। सीबीआई अभी जांच कर रही है बताया जाता है कि पूरे देश में 100 से अधिक लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

यह दूसरा मौका जब एनटीए की नीट परीक्षा पर प्रश्न लग
रहे हैं इससे पूर्व 2024 की परीक्षा पर भी सवाल उठे थे।

दरअसल देश में एक तबका ऐसा है कि उसे अपने बच्चों डॉक्टर बनाना है क्योंकि मेडिकल डॉक्टर की आय का कोई ठिकाना नहीं है देश में कुल निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एक लाख सीट है और 22 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी।यानि कड़ी प्रतियोगिता है।इस लिए लोग गलत रास्ते अपनाते हैं । दिनेश और मांगीलाल के घर चार बच्चों को ,2024, में प्रवेश मिला है।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर हमेशा से ही गिद्धों की नजर रही है।इन गिद्धों में दलाल, राजनेता,नौकरशाह शामिल रहे हैं।इनका जाल राज्यों की यूपीएससी, सीएससी,कुछ हद तक यूपीएससी,सेना भर्ती तक फैला हुआ है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा भी इसमें शामिल है। बताया जाता है कि ये लोग सबसे पहले पेपर सेटर से बात करते हैं फिर पता लगाते हैं कि पेपर किस प्रेस में प्रकाशित हो रहा है।बस यही एक कमजोर कड़ी से सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करते हैं। और मनमाने तरीके से बेच देते हैं।इसमें प्रतिभा शील छात्र पीछे रह जाते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इन पेपर को कलेक्टर के हवाले कर देते हैं और कलेक्टर इन्हें कोतवाली में रख देता है मगर रात को ही लिफाफे को खोल कर पेपर को फोटो कॉपी कर या पीडीएफ बनाकर सर्कुलेट करदेते है। नेटवर्क इतना तगड़ा है कि प्रत्येक राज्य, महानगर,बड़े शहरों से जिले मुख्यालय तक पहुंचा ही नहीं देते बल्कि रात में ही ऑनलाइन पैसा भी ट्रांसफर कर दिया जाता है।

ब्लॉग

चिंतन शिविर: साझा दृष्टिकोण के ज़रिए भारत में खेलों के भविष्य को दिशा देना

पुलेला गोपीचंद

दो चिंतन शिविरों का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त करने के बाद, मैं भरोसे के साथ कह ??सकता हूँ कि यह आज भारतीय खेल जगत की सबसे सामयिक और असरदार पहलों में से एक है। हम अपने राष्ट्र की खेल यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, एक ऐसा मोड़ जहाँ इरादा, निवेश और प्रेरणा अभूतपूर्व रूप से एक साथ मिल रहे हैं।

पिछले एक दशक में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत में खेल हाशिये से मुख्यधारा में आ गया है। इसके महत्व के प्रति भी साफ तौर पर राष्ट्रीय जागरूकता देखी जा सकती है, न केवल एक प्रतिस्पर्धी गतिविधि के रूप में, बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव के साधन के रूप में भी। आज, हम एक विशाल और विविध तंत्र देख रहे हैं, जहां राज्य सरकारें, गैर-सरकारी संगठन, निगम, संघ और ज़मीनी स्तर के संस्थान सभी मिलकर खेलों के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं।

चिंतन शिविर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाता है। खेल अपने आप में कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिनमें विनिर्माण, मनोरंजन, फिटनेस, मीडिया और शिक्षा शामिल हैं। यह शिविर इन सभी क्षेत्रों को एक साथ लाने में मदद करता है, जिससे एक साझा दृष्टिकोण बनता है, जो दीर्घकालिक सफलता के लिए बेहद ज़रुरी है। यह देश के सामूहिक दृष्टिकोण को सामने लाता है और साथ ही विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करता है, जिससे अनुकरण और नवाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है।

चिंतन शिविर महज एक सम्मेलन से कहीं बढ़कर, एक शिक्षण तंत्र है। यह इसमें शामिल होने वाले लोगों को विचारों का आदान-प्रदान करने, चुनौतियों को समझने और मिलकर समाधान विकसित करने का अवसर देता है। यह एक शक्तिशाली प्रेरक के रूप में भी काम करता है, सफलता की तमाम कहानियों को सामने लाता है और इस विचार को और पुख्ता करता है कि भारत में खेल महज़ विशिष्ट पदकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भागीदारी, समावेशिता और राष्ट्र निर्माण भी शामिल है।

फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन और साइक्लिंग प्रतियोगिताओं जैसी सामुदायिक गतिविधियों ने खेल के प्रति हमारे नज़रिए को नया रूप दिया है। आज के वक्त में जोर ₹सभी के लिए खेल₹ के साथ-साथ, उच्चतम स्तर पर उत्कृष्टता पर है। पदक जीतने की आकांक्षाएं और व्यापक भागीदारी अब अलग-अलग मुद्दे नहीं हैं, बल्कि वे एक ही प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

श्रीनगर में शिविर का आयोजन करने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस शहर की शांत सुंदरता न केवल खेलों की विचारधारा के लिए एक मनोरम पृष्ठभूमि प्रदान करती है, बल्कि शांत चिंतन का भाव भी देती है, जो सार्थक संवाद के लिए बेहद ज़रुरी है।

इस चिंतन शिविर का एक अहम केंद्र बिंदु श्रीनगर खेल संकल्प को अपनाना था। यह संकल्प महज़ एक आशय का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि यह एक एकीकृत ढांचा है, जो भारतीय खेल जगत के सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को एक साथ बांधता है। साझा लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करके, यह एक ऐसा रोडमैप तैयार करता है, जो विखंडन के बजाय सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

श्रीनगर खेल संकल्प की असली ताकत विभिन्न भागीदारों—सरकारों, संघों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक मंच पर लाने की क्षमता में निहित है। यह इस विचारधारा को और पुख्ता करता है कि भारत के खेल जगत का उत्थान अलग-थलग प्रयासों से नहीं हो सकता। इसके बजाय, इसे एक समन्वित, सहयोगात्मक दृष्टिकोण से संचालित किया जाना चाहिए, जहां संसाधनों, ज्ञान और विशेषज्ञता को एक साथ लाया जाए।

भारत को 2036 तक ओलंपिक खेलों में शीर्ष 10 देशों में शामिल होने की अपनी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए यह समन्वय बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व स्तरीय एथलीट तैयार करने के लिए न केवल प्रतिभा की ज़रुरत होती है, बल्कि एक सुचारू तंत्र की भी आवश्यकता होती है, जिसमें जमीनी स्तर पर पहचान, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा, उत्कृष्ट कोचिंग, प्रतिस्पर्धा का अनुभव और निरंतर वित्तीय एवं संस्थागत समर्थन शामिल हैं। संकल्प वही रणनीतिक कड़ी है, जो इन सभी तत्वों को एक सुसंगत प्रणाली में जोड़ सकता है।

इन वार्ताओं से जो बात सबसे अधिक उभरकर सामने आई है, वह है इस व्यवस्था में मौजूद आशावाद। सभी का यह मानना ??है कि भारत का खेल भविष्य उज्ज्वल है और सहयोग से हम एक सशक्त, समावेशी और उच्च प्रदर्शन वाली खेल संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं।

चिंतन शिविर कई मायनों में एक अनूठा प्रयोग है, लेकिन यह पहले से ही सफल साबित हो रहा है। यह संवाद, समन्वय और आपसी समझ के महत्व को दर्शाता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए, ऐसे मंच न केवल लाभकारी हैं, बल्कि आवश्यक भी हैं।

अगर हम वैश्विक खेल मंच पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को सही मायने में साकार करना चाहते हैं, तो इन संवादों का जारी रहना और इन्हें सामूहिक कार्रवाई से मदद मिलना भी ज़रुरी है। श्रीनगर खेल संकल्प हमें वह दिशा प्रदान करता है। चिंतन शिविर हमें वह मंच प्रदान करता है। ये दोनों मिलकर भारत को अपनी खेल संबंधी आकांक्षाओं को स्थायी ओलंपिक सफलता में बदलने के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करते हैं।

(लेखक भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच हैं)

प्रेमी को मारा, टुकड़े किए और जलाया, इंटरनेट से सीखा ये तरीके; यूट्यूबपर देखी सजा की अवधि-जेल की सुविधाएं

आर्यावर्त संवाददाता

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने प्रेम, विश्वासघात और क्रूरता की पराकाष्ठा को पार कर दिया गया। अवैध संबंधों के चलते युवक की बेरहमी से हत्या की गई। इसके बाद शव के टुकड़े किए गए। 8 मई से लापता चल रहे युवक के मामले में पुलिस ने जिस तरह से हत्याकांड का खुलासा किया है, वह किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। हैरत की बात यह है कि हत्या का राज खोलने में यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री ने अहम भूमिका निभाई।

यह पूरा घटनाक्रम फतेहपुर जिले के बकेवर थाना क्षेत्र का है। 20 वर्षीय विजय निषाद 8 मई से लापता था। परिजनों द्वारा 11 मई को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस जांच में जुटी। जांच के दौरान

पुलिस ने विजय की कॉल डिटेल खंगाली तो उसमें हमीरपुर की किरन के साथ प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ। इसी नंबर पर अधिक बात होनी की जानकारी लगी। इस क्लू से जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने दंपती को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ।

प्रेम संबंध में पति कामता और पत्नी किरन ने मिलकर प्रेमी विजय को रास्ते से हटाने की खूनी साजिश रची थी। साजिश के तहत, किरन ने आठ मई को विजय को अपने घर हमीरपुर बुलाया। यहीं कामता ने अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए लकड़ी की चौखट से वार कर विजय की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद, शव को ठिकाने लगाने के लिए

जांच में सामने आया है कि विजय का किरन देवी से प्रेम-प्रसंग था। इसे लेकर पति कामता प्रसाद निषाद उससे रंजिश रखता था। आठ मई को किरन ने विजय को घर बुलाया। यहां पहले से मौजूद कामता प्रसाद ने लकड़ी के चौखट से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद ग्राइंडर मशीन से हाथ-पैर काटकर शव को बोरे में भरकर पेट्रोल डालकर जंगल में जला दिया था। -अभिमन्यु मांगलिक, एसपी।

उन्होंने ग्राइंडर से शव के टुकड़े कर दिए। इसके बाद टुकड़ों को कानपुर के रेऊना थाना इलाके के एक जंगल में ले जाकर जला दिया गया, ताकि कोई सुराग न मिले।

पुलिस ने जब किरन से पूछताछ की, तो लंबी बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आईं, जिनसे शक गहरा गया। इसके बाद, पुलिस ने जब किरन और कामता के मोबाइल फोन की यूट्यूब सर्च हिस्ट्री खंगाली, तो सारे राज खुल गए।

चौंकाने वाली बात यह थी कि पति-पत्नी ने मिलकर यूट्यूब पर हत्या की सजा, फांसी का कानून, और पुलिस एनकाउंटर जैसी जानकारी जुटाई थी। इस सर्च हिस्ट्री ने सीधे तौर पर हत्या की योजना और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने की मंशा की ओर इशारा किया।

यूट्यूब देखकर रची कत्ल की साजिश, इंटरनेट से सीखे सबूत मिटाने के तरीके

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी दंपती ने हत्या की साजिश यूट्यूब देखकर रची थी। पूछताछ में दोनों ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने इंटरनेट और यूट्यूब के जरिये हत्या के बाद सबूत मिटाने के तरीके, पकड़े जाने पर लगने वाली धाराओं, उनसे बचने के उपाय, सजा की अवधि और जेल में मिलने वाली सुविधाओं तक की जानकारी सर्च की थी।

तस्वीर देख खौल गया था पति का खून

आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि विजय की उसके पड़ोसी के यहां रिश्तेदारी थी। इसके चलते उसका गांव आना-जाना था और इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग हो गया। विजय बार-बार उसके मोबाइल पर फोन करता था। इससे पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा। महिला ने बताया कि परेशान होकर उसने पति के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। महिला का आरोप है कि विजय ने कुछ महीने पहले किसी तीसरे के शक में उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थीं। यह तस्वीर सोशल मीडिया के जरिये गुजरात में रह रहे उसके पति तक पहुंच गई थीं। इसके बाद पति के नौकरी छोड़कर गांव लौटने के बाद विवाद बढ़ गया।

हत्या में और लोगों के शामिल होने का आरोप

विजय निषाद के परिजन ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि हत्या में केवल दंपती ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी शामिल हैं। परिजन का कहना है कि गांव के लोगों ने विजय को कई लोगों द्वारा पीटे जाने की बात बताई थी। उनका यह भी आरोप है कि आरोपी महिला गर्भवती है और पति के पैर में रॉड लगी है। ऐसे में दोनों अकेले पूरी घटना को अंजाम नहीं दे सकते।

20 परीक्षा केन्द्रों पर होगी टीजीटी की परीक्षा

जौनपुर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) परीक्षा को जनपद में सकुशल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्री सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा कार्य में तैनात सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट को परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 तथा आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के 20 परीक्षा केन्द्रों पर 03 एवं 04 जून को दो पालियों में आयोजित होने वाली टीजीटी परीक्षा के लिए सेक्टर एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है।

तुषार त्यागी मर्डर केस : 'पति को गोली मार दी है...' पत्नी को कॉल कर बताया, मेरठ में कार के अंदर मिली लाश

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक का नाम तुषार त्यागी है। शुरुआती जांच में मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि तुषार की हत्या जमीन और संपत्ति के विवाद में की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

घटना मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के कैली गांव की है, जहां एक खेत में खड़ी स्कॉर्पियो कार के अंदर तुषार त्यागी का शव मिला। बताया जा रहा है कि तुषार की पत्नी शिखा त्यागी और उसकी बहन गिन्नी त्यागी रातभर उसकी तलाश करती रहीं। काफी देर तक खोजबीन के बाद वे मेरठ पहुंचीं, जहां उन्हें खेत में खड़ी तुषार की गाड़ी दिखाई दी।

जब दोनों ने गाड़ी के अंदर देखा तो तुषार खून से लथपथ हालत में पड़ा था। यह देखकर परिवार के होश उड़ गए। बहन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची

पुलिस ने तुषार को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक, हत्या से पहले तुषार ने अपनी पत्नी को फोन कर बताया था कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है। परिवार का आरोप है कि हापुड़ निवासी अरविंद त्यागी उर्फ बिट्टू ने तुषार को फोन कर बुलाया था। उसने कहा था कि खाना लेकर आ जाओ। इसके बाद तुषार घर से निकल गया। आरोप है कि बिट्टू और उसके साथ मौजूद कुछ अन्य लोगों ने मिलकर तुषार का अपहरण कर लिया। इसी दौरान तुषार ने अपनी पत्नी शिखा को फोन कर बताया कि उसे जबरन उठा लिया गया है। इसके बाद परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। शिखा को किसी तरह अरविंद उर्फ बिट्टू का मोबाइल नंबर मिला। जब उसने फोन किया तो बिट्टू ने कथित तौर पर कहा कि तुषार को गोली मार दी है और इसके बाद फोन बंद कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस को मृतक की पत्नी और बहन ने बताया कि परिवार में लंबे समय से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। उन्होंने इस मामले में तुषार के पिता पर भी शक जताया है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि तुषार की मां के नाम काफी संपत्ति है और इसी संपत्ति को लेकर पहले भी विवाद हो चुके हैं। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें मृतक के पिता का नाम भी शामिल है। फिलहाल सभी संदिग्ध फरार हैं और उनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।

मोटर साइकिलों की भिड़ंत में तीन घायल

जौनपुर। जफराबाद थाना क्षेत्र के विजय प्रताप स्कूल के पास दो मोटर साइकिलों की भिड़ंत हो गई जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये । एक की हालत गंभीर बताई जा रही है जिसको वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है । जगदीश उपाध्याय उम्र 60 वर्ष निवासी रसूलपुर थाना जलालपुर अपने नाती आकाश पांडेय 21 वर्ष पुत्र कमलेश के साथ बाईक से जौनपुर शहर में दवा लेने आए थे दवा लेकर वापस घर जा रहे थे कि जैसे ही वह जफराबाद थाना के 100 मीटर पहले विजय प्रताप स्कूल के पास पहुंचे सामने से आ रही बाइक लेकर आनंद प्रकाश 24 वर्ष पुत्र महेंद्र निवासी ग्राम पुरोसारा टोली थाना घाघरा जनपद झारखंड कि सामने से टक्कर हो गई जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार तिवारी ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया जहां पर आकाश की हालत गम्भीर देखते हुए डॉक्टर उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया हैं और बाकी दो लोगों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।

गर्दन काटकर हत्या, फिर नमक डालकर गड्ढे में दबाया धड़, सिर नहर में फेंकने की बात कबूली, ऐसे खुला राज

आर्यावर्त संवाददाता

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के बेहड़ा अस्सा गांव से लापता हुए 36 वर्षीय विकसित उर्फ रॉकी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए आरोपी मोंटी त्यागी की निशानदेही पर कादीपुर के जंगल से सिर कटा शव बरामद किया है। बताया गया कि पिछले महीने 18 मई को रॉकी अपनी पत्नी के साथ घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इसके बाद 20 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान मामला हत्या में बदल गया।

पुलिस आरोपी को लेकर कादीपुर के जंगल पहुंची, जहां जेसीबी की मदद से करीब आठ फीट गहरा गड्ढा खुदवाया गया। गड्ढे से रॉकी का सिर कटा धड़ बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार शव नग्न अवस्था में मिला और उसे गलाने के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में नमक भी डाला गया

था। घटनास्थल से एक आधार कार्ड भी बरामद हुआ है, जिसे जांच का महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है।

सिर नहर में फेंकने की बात कबूली

पूछताछ में आरोपी ने कथित रूप से बताया कि हत्या के बाद शव से सिर अलग कर दिया गया और उसे नहर में फेंक दिया गया। पुलिस अब सिर की तलाश में अभियान चला रही है। देर रात तक सिर बरामद नहीं हो सका था। पुलिस का कहना है कि आरोपी के दावों की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर परखा जाएगा।

पत्नी, बेटे और पुत्रवधू पर गंभीर आरोप

जांच में मृतक की पत्नी रेणू, सौतेले बेटे बादल और पुत्रवधू निशा के नाम सामने आए हैं। तीनों के खिलाफ अपहरण और हत्या से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार वारदात के पीछे पारिवारिक विवाद प्रमुख कारण माना जा रहा है। हालांकि सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है।

मोबाइल ऑन कर पुलिस को करते रहे गुमराह

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने पुलिस को भ्रमित करने के लिए रॉकी के मोबाइल फोन को समय-समय पर चालू रखा, ताकि यह लगे कि वह जीवित है। पुलिस ने कई राज्यों में दबिश दी, लेकिन आरोपी लगातार ठिकाने बदलते रहे। अंततः मोंटी त्यागी की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।

बड़ौत में हत्या, जंगल में दफनाया शव

पुलिस जांच के अनुसार हत्या बड़ौत क्षेत्र में की गई थी। इसके बाद आरोपियों ने घटनास्थल की सफाई की और शव को वाहन में ले जाकर कादीपुर के जंगल में दफना दिया। शव को ठिकाने लगाने के लिए गड्ढा खुदवाया गया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। पुलिस अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।

'दूल्हा हत्याकांड' में दो की जमानत याचिका खारिज

जौनपुर। शादी के जश्न के बीचो-बीच दूल्हे की सरेआम हत्या कर सनसनी फैलाने के आरोपियों को अदालत से बड़ा झटका लगा है। ज्ञात हो कि खेतासराय थाना क्षेत्र के बेहद सनसनीखेज और रूह कंपा देने वाले 'दूल्हा हत्याकांड' में जिला जज सुशील कुमार शशि ने जुर्म की खौफनाक गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी शोले राजभर (निवासी शैफपुर, सरायख्वाजा) और विकास यादव (निवासी मोजीपुर, खुटहन) की जमानत याचिका को सिरे से खारिज (निरस्त) कर दिया है।यह महज एक अपराध नहीं, बल्कि एक हंसते-खेलते परिवार को ताउम्र का दर्द देने वाली खूनी साजिश थी। अभियोजन पक्ष की ओर से दमदार पैरवी करते हुए डीजीसी फौजदारी लाल बहादुर पाल ने कोर्ट के सामने इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात की परत दर परत खोली।मृतक आजाद बिंद की शादी सोनी बिंद से तय हुई थी।

सूर्या हत्याकांड के बाद एक्शन मोड में प्रशासन, खोड़ा में 3 मदरसे सील, पीएसी-आरएएफ तैनात

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले के खोड़ा इलाके में सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' के तहत तीन दिनों से इलाके में हिस्ट्रीशीटरों, बदमाशों और असामाजिक तत्वों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस टीमें चिन्हित अपराधियों के घरों पर दबिश दे रही हैं, जबकि संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर उनका सत्यापन भी किया जा रहा है। वहीं मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खोड़ा के तीन मदरसों को सील कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में PAC और RAF के जवान तैनात रहे।

डीएम रविन्द्र कुमार मांदड़ का कहना है कि इलाके में अपराध और

असामाजिक गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन कैमरों, स्निफर डॉग्स और अन्य आधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है। संवेदनशील इलाकों और कई मकानों की छतों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।

बता दें कि यह अभियान सूर्या हत्याकांड के बाद शुरू किया गया है। मामले के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में डर पैदा करने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

मदरसों पर नोटिस चस्पा किया गया

डीएम रविन्द्र कुमार मांदड़ ने बताया कि इलाके में जो भी अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। करीब तीन ऐसे मदरसों को चिन्हित किया गया है, जो अवैध रूप से चल रहे हैं। उन पर कार्रवाई की गई है। उन्हें सील किया गया है और बाकायदा नोटिस चस्पा कर जवाब एक हफ्ते के अंदर मांगा गया है। अवैध मदरसा इसलिए था, क्योंकि इसका पंजीकरण नहीं था, न ही अल्पसंख्यक बोर्ड में रजिस्टर था। प्रशासन कहना है कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए इस तरह का 'ऑपरेशन क्लीन' लगातार चलाया जाएगा।

बता दें कि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस ऑपरेशन को तीन मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित किया गया है। पहला, डोर-टू-डोर जाकर अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन करना। दूसरा, अपराध से जुड़े लोगों को थाने बुलाकर उन्हें चेतावनी देना और तीसरा, सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों की जांच कर कार्रवाई करना। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के साथ-साथ अवैध गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाना है।

भारी संख्या में PAC और RAF के जवान तैनात

खोड़ा क्षेत्र में सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल के साथ PAC और RAF को भी मौके पर बुलाया गया है। प्रशासन की ओर से पूरे इलाके में फ्लैग मार्च निकाले जाने की तैयारी की गई है। अधिकारियों का मानना है कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी से कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।

1410 पैमाइश और 537 पत्थरगड्डी के मामले निपटे

जौनपुर। जिले में भूमि पैमाइश और पत्थरगड्डी (सीमांकन) के वर्षों से लंबित मामलों का अब अभियान चलाकर निस्तारण किया जा रहा है। जिले की छह तहसीलों में कुल 5389 ऐसे मामले लंबित थे, जिनमें से हाल ही में हुई प्रशासनिक कार्रवाई के बाद एक सप्ताह के भीतर लगभग 450 आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है।यह कार्रवाई सदर तहसील के राजस्व निरीक्षक रमेशचंद्र कुरील को लापरवाही के आरोप में निलंबित किए जाने के बाद तेज हुई है। आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई न होने के कारण लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिससे भूमि विवादों में भी वृद्धि हो रही थी।जिलाधिकारी की सख्ती के बाद अब तहसील प्रशासन सक्रिय हो गया है। सभी छह तहसीलों में अभियान के तहत अब तक 1410 पैमाइश और 537 पत्थरगड्डी के मामले निपटाए जा चुके हैं। पुलिस और राजस्व की टीमें अन्य लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए भी मौके पर पहुंच रही हैं।

जिस पुल से कार गिरने से हुई थी तीन लोगों की मौत, वो आज भी अधूरा, फाइलों में अटका काम

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। बदायूं के दातागंज क्षेत्र में रामगंगा नदी पर मुढ़ा पुख्ता क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत और विस्तार का मामला फिर फंस गया है। लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम की ओर से भेजे गए 104 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को शासन की वित्त समिति ने पांचवीं बार आपत्तियों के साथ वापस कर दिया है। लगातार हो रही देरी के कारण पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आगामी बाढ़ सीजन से पहले पुल के चालू होने की उम्मीद लगभग खत्म होती नजर आ रही है। हालांकि विभाग ने शुक्रवार को फिर फाइल शासन को भेज दी है।

दातागंज क्षेत्र के गांव मुढ़ा पुख्ता और फरीदपुर के बीच रामगंगा नदी पर बने इस पुल का एक हिस्सा सितंबर 2023 में आई भीषण बाढ़ में बह गया था। इसके बाद से पुल

अधूरा पड़ा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। 24 नवंबर 2024 को कार गिरने से उसमें सवार तीन युवकों की मौत हो गई थी। ये लोग गूगल मैप के सहारे इस रास्ते पर कहीं जा रहे थे। पिछले डेढ़ वर्ष से आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुल बंद होने के कारण लोगों को कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।

जनता को झेलनी पड़ रही परेशानी

शासन और विभाग के बीच फाइलों का खेल चल रहा है, जबकि परेशानी जनता झेल रही है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर पुल की लंबाई बढ़ाने और एप्रोच मार्ग को अधिक सुरक्षित बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसके लिए 104 करोड़ रुपये का संशोधित एस्टीमेट शासन को भेजा गया, लेकिन वित्त समिति बार-बार अलग-अलग बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांग रही है। अब पांचवीं बार फाइल वापस भेजे जाने से विभागीय अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना से जुड़ी सभी जानकारियां शासन को उपलब्ध कराई जा चुका है। एस्टीमेट रिवाइज के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, वह दे दी गई है और पत्रावली भेज दी गई है।

कार गिरने से हुई थी तीन लोगों की मौत

12 सितंबर 2023 को रामगंगा में आई भीषण बाढ़ के दौरान पुल का संपर्क मार्ग पूरी तरह से कट गया था। इसके बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों की आवाजाही ठप हो गई थी। मरीजों को अस्पताल ले जाना, बच्चों का स्कूल जाना और किसानों का खेतों तक पहुंचना बेहद कठिन हो गया था। इसके अलावा, 24 नवंबर 2024 को गुरुग्राम से फरीदपुर में एक शादी समारोह में जा रहे कार सवार मैनपुरी के बिछवां निवासी अमित सिंह (38), फर्रुखाबाद के एमादपुर हीरामन निवासी अजीत कुमार (35) और उनके चचेरे भाई नितिन (30) इस अधूरे पुल से कार सहित गिर गए थे, जिससे तीनों की मौत हो गई थी। तीनों गूगल मैप के सहारे रास्ता तय कर रहे थे। हादसे के बाद गूगल को अपने मैप से इस पुल का रास्ता हटाना पड़ा था। लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन नरेश कुमार ने बताया कि रामगंगा नदी पर बने मुढ़ा पुख्ता पुल के संबंध में शासन की ओर से कुछ जानकारियां मांगी गई है। उनके जवाब बनाकर दोबारा से शासन को भेज दिए गए हैं।

200 मीटर बढ़ेगी पुल की लंबाई

पुल के स्थायी समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से आईआईटी रुड़की से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई थी। टीम ने जनवरी 2025 में मॉडल स्टडी कर चार माह बाद अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपी। रिपोर्ट में पुल की लंबाई 200 मीटर बढ़ाने, 400 मीटर का नया संपर्क मार्ग बनाने और करीब तीन से चार किलोमीटर अतिरिक्त संपर्क मार्ग विकसित करने की सिफारिश की गई थी। आईआईटी की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 104 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। अब जल्द ही लोक निर्माण विभाग की ओर से निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

पहले 42 करोड़ की लागत से बना था पुल

दातागंज तहसील के गांव मुढ़ा पुख्ता और फरीदपुर के बीच रामगंगा नदी पर करीब पांच साल पहले 42 करोड़ रुपये की लागत से 700 मीटर लंबा पुल बनाया गया था। इस पुल के बनने से दातागंज और फरीदपुर के बीच की दूरी काफी कम हो गई थी। हालांकि, वर्ष 2023 में आई भीषण बाढ़ के दौरान रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से फरीदपुर की ओर का करीब 180 मीटर लंबा संपर्क मार्ग 12 सितंबर को बह गया था, जिससे पुल बेकार हो गया था।

फेसबुक पर दोस्ती पड़ी महंगी : युवती ने वकील को दिखाए सुनहरे सपने, फिर ठग लिए 15 .45 लाख रुपये

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। बरेली में वकील को एक युवती ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और दोस्ती कर ली। फिर सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया और शेयर व क्रिप्टो करेंसी में उनके 15.45 लाख रुपये लगवा दिए। बाद में महिला ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिया तो पता लगा कि वह ठगी का शिकार हो चुके हैं। पीड़ित की तहरीर पर साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया है।

नवाबगंज इलाके के निवासी अधिवक्ता अजय प्रकाश ने साइबर क्राइम थाना प्रभारी धनंजय पांडेय को बताया कि इसी साल मार्च में कोमल अग्रवाल नाम से एक महिला ने उन्हें फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अजय प्रकाश ने कोमल को फेसबुक से जोड़ लिया। कोमल अग्रवाल ने खुद को अजमेर का निवासी बताया और दोस्ती बढ़ाकर बात करना शुरू कर दिया। उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए क्रिप्टो व शेयर बाजार में निवेश करने पर तगड़े मुनाफे का झांसा दिया।

कई बार ट्रांसफर कराई रकम

कोमल ने रविंद्र भाटी नाम के युवक से संपर्क करा दिया। कोमल व रविंद्र ने मिलकर धीरे-धीरे अजय प्रकाश से 1544930 रुपये ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद दोनों ने उनका नंबर ब्लॉक कर अपने नंबर बंद कर लिए। जानकारी करने पर पता लगा कि ठगी हो चुकी है। साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश के ये साड़ी लुक वेडिंग सीजन के लिए हैं बेस्ट

साउथ एक्ट्रेस के एथनिक लुक शानदार होते हैं। वेडिंग सीजन में स्टाइल दिखाना हो या फिर प्योर ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना हो, एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश के साड़ी डिजाइन से इंस्पिरेशन ली जा सकती है। चलिए इस स्टोरी में देख लेते हैं उनके कुछ साड़ी लुक्स।

रिसेप्शन वाले दिन के लिए आप कीर्ति सुरेश की तरह ब्लैक कलर की सीक्वेंस रेडी टु वियर साड़ी पहन सकती हैं। एक्ट्रेस ने स्टोन के ड्रॉप ईयररिंग पहने हैं। ग्लैम बेस के साथ उन्होंने स्मोकी आइज मेकअप किया है। एक्ट्रेस ने बालों को कर्ल करके पोनीटेल बनाई है और साड़ी के साथ हाई हील्स वियर की हैं। इस तरह का लुक स्पेशली गर्ल्स के लिए बेस्ट रहेगा।

रिसेप्शन वाले दिन के लिए आप कीर्ति सुरेश की तरह ब्लैक कलर की सीक्वेंस रेडी टु वियर साड़ी पहन सकती हैं। एक्ट्रेस ने स्टोन के ड्रॉप ईयररिंग पहने हैं। ग्लैम बेस के साथ उन्होंने स्मोकी आइज मेकअप किया है। एक्ट्रेस ने बालों को कर्ल करके पोनीटेल बनाई है और साड़ी के साथ हाई हील्स वियर की हैं। इस तरह का लुक स्पेशली गर्ल्स के लिए बेस्ट रहेगा।

वेडिंग डे हो या फिर रिसेप्शन। कीर्ति सुरेश का ये लुक परफेक्ट रहेगा। एक्ट्रेस ने आलमंड कलर की ग्लिटर साड़ी वियर की है, जिसके साथ उन्होंने मल्टिकलर ब्लाउज से कंट्रास्ट क्रिएट किया है। बालों को वन साइड लाइट कर्ल करके खुला छोड़ा है और बोल्ड मेकअप लुक है। पर्ल की ज्वेलरी परफेक्ट लुक दे रही है।

वेडिंग डे हो या फिर रिसेप्शन। कीर्ति सुरेश का ये लुक परफेक्ट रहेगा। एक्ट्रेस ने आलमंड कलर की ग्लिटर साड़ी वियर की है, जिसके साथ उन्होंने मल्टिकलर ब्लाउज से कंट्रास्ट क्रिएट किया है। बालों को वन साइड लाइट कर्ल करके खुला छोड़ा है और बोल्ड मेकअप लुक है। पर्ल की ज्वेलरी परफेक्ट लुक दे रही है।

वियर की है, जिसके साथ उन्होंने मल्टिकलर ब्लाउज से कंट्रास्ट क्रिएट किया है। बालों को वन साइड लाइट कर्ल करके खुला छोड़ा है और बोल्ड मेकअप लुक है। पर्ल की ज्वेलरी परफेक्ट लुक दे रही है।

आपको बिल्कुल देसी ठाठ चाहिए तो कीर्ति सुरेश का ये साड़ी लुक वेडिंग डे के लिए बेस्ट है। उन्होंने गोल्डन साड़ी वियर की है, जिसके साथ वाइट कलर का गोल्डन जरी वाला ब्लाउज पहना है। साथ में जड़ाऊ नेकलेस और पोल्की झुमके पेयर किए हैं। स्लीक बन बनाकर गजरे से डेकोरेट किया है।

आपको बिल्कुल देसी ठाठ चाहिए तो कीर्ति सुरेश का ये साड़ी लुक वेडिंग डे के लिए बेस्ट है। उन्होंने गोल्डन साड़ी वियर की है, जिसके साथ वाइट कलर का गोल्डन जरी वाला ब्लाउज पहना है। साथ में जड़ाऊ नेकलेस और पोल्की झुमके पेयर किए हैं। स्लीक बन बनाकर गजरे से डेकोरेट किया है।

कीर्ति सुरेश का ये साड़ी लुक हल्दी सेरेमनी के लिए बेस्ट है। उन्होंने गोल्डन बॉर्डर वाली लाइठ वेट यलो साड़ी पहनी है, जिसके साथ हाई नेक कट स्लीव ब्लाउज वियर किया है। गोल्डन विंटेज ज्वेलरी के साथ उन्होंने फ्लॉलेस मेकअप लुक रखा है और बालों को खुला छोड़ा है। उनका ये लुक फ्लॉलेस है।

कीर्ति सुरेश का ये साड़ी लुक हल्दी सेरेमनी के लिए बेस्ट है। उन्होंने गोल्डन बॉर्डर वाली लाइठ वेट यलो साड़ी पहनी है, जिसके साथ हाई नेक कट स्लीव ब्लाउज वियर किया है। गोल्डन विंटेज ज्वेलरी के साथ उन्होंने फ्लॉलेस मेकअप लुक रखा है और बालों को खुला छोड़ा है। उनका ये लुक फ्लॉलेस है।

पेस्टल थीम पसंद है तो ट्रेंडी लुक पाने के लिए कीर्ति सुरेश की तरह आप लाइट मिंट कलर की साड़ी वियर कर सकती हैं। एक्ट्रेस की साड़ी पर हैवी एम्ब्रॉयडरी है, जिसे परफेक्ट मैच देने के लिए उन्होंने नेकपीस भी काफी भारी चुना है। ईयररिंग और बैंगल्स भी लुक को रिच टच दे रहे हैं। सिंपल बन में गजरा लगाकर लुक कंप्लीट किया गया है।

पेस्टल थीम पसंद है तो ट्रेंडी लुक पाने के लिए कीर्ति सुरेश की तरह आप लाइट मिंट कलर की साड़ी वियर कर सकती हैं। एक्ट्रेस की साड़ी पर हैवी एम्ब्रॉयडरी है, जिसे परफेक्ट मैच देने के लिए उन्होंने नेकपीस भी काफी भारी चुना है। ईयररिंग और बैंगल्स भी लुक को रिच टच दे रहे हैं। सिंपल बन में गजरा लगाकर लुक कंप्लीट किया गया है।

स्किन और ब्रेन के लिए जरूरी है ओमेगा-3 फैटी एसिड, एक्सपर्ट की बताई ये चीजें खाएं

सेहतमंद रहने के लिए कई तरह के पोषक तत्व विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी होते हैं। जिनसे शरीर को एनर्जी मिलती है। ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर के लिए जरूर न्यूट्रिएंट्स में से एक है। जो शरीर को अलग-अलग कार्य के लिए जरूरी होता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड को लेकर लोगों का मानना है कि ज्यादातर यह नॉन-वेज, खासकर के मछली में पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह कई शाकाहारी चीजों में भी पाया जाता है। जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं।

ओमेगा-3 फैटी एसिड स्किन को हेल्दी रखने के साथ ही ब्रेन और हार्ट के लिए भी बहुत जरूरी होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में एक्सपर्ट से कि ओमेगा-3 फैटी एसिड हमारे लिए क्यों जरूरी है, शरीर में इसकी कमी होने पर किस तरह के लक्षण नजर आते हैं और कौन-से शाकाहारी फूड्स में यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है।

ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर के लिए क्यों जरूरी है?

अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में कंसलटेंट जनरल फिजिशियन डॉक्टर अंकित पटेल का कहना है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड एक जरूरी पोषक तत्व है। इसे शरीर खुद नहीं बना सकता, इसलिए इसे हमें खाने के जरिए लेना पड़ता है। यह हमारे दिमाग, हार्ट, आंखों और जोड़ों को हेल्दी बनाएं रखने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड स्किन को हेल्दी रखने के लिए भी जरूरी होता है, ये एजिंग साइंस से बचाव करने में मदद करता है। शरीर में अगर ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी हो जाए, तो इससे याददाश्त कमजोर होना, मूड चिड़चिड़ा, ड्राई और डैमेज स्किन जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बच्चों में इसकी कमी से मानसिक विकास रुक सकता है।

डाइट में शामिल करें ये चीजें

ओमेगा-3 मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं ALA, EPA और DHA।शाकाहारी फूड्स की बात करें तो, फ्लैक्ससीड यानी की अलसी के बीज, चिया सीड्स, अखरोट, सोयाबीन, कनोला ऑयल और हरी पत्तेदार सब्जियों में यह पाया जाता है। इनमें ALA मिलता है, जो शरीर में सीमित मात्रा में ही DHA और EPA में बदलता है, जो शरीर के लिए ज्यादा असरदार होते हैं।

अंडों और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में भी यह थोड़ी मात्रा में ओमेगा-3 पाया जाता है। शाकाहारी लोगों के लिए सप्लीमेंट्स जैसे अल्गी ऑयल एक अच्छा विकल्प है। इसलिए अपनी डाइट में ओमेगा-3 से भरपूर चीजें शामिल करना जरूरी है, ताकि शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहें और आप हेल्दी रहें।

मानसून में केरल के इस हिडन प्लेस में ले बीच का मजा, जेब पर भी नहीं पड़ेगा असर

जब भी छुट्टियों में घूमने-फिरने की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में गोवा, शिमला-मनाली, जयपुर जैसी जगहें आती है। पहाड़ और वादियां देखने के लिए लोग हिल स्टेशन का रूख करते हैं। वहीं समुंद्र का मजा लेने के लिए लोग गोवा जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवा नहीं बल्कि इससे भी खूबसूरत एक ऐसी जगह है जो आपको बीच का असली मजा देती है। जी हां, केरल में एक ऐसा हिडन जेम है, जो अभी भी भीड़-भाड़ से दूर है और अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, शांत माहौल और सुंदर बीचों के लिए जाना जाता है।

हम बात कर रहे हैं वर्कला की। वर्कला एक छोटा लेकिन बेहद खास समुद्र किनारा है, जो तिरुवनंतपुरम से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां न तो गोवा जैसी भीड़ होती है, न ही ऊंचे होटल बिल्स। बल्कि वर्कला उन लोगों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो सुकून चाहते हैं, नेचर के करीब रहना चाहते हैं और कम बजट में एक शानदार ट्रिप का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। चलिए जानते हैं वर्कला के बारे में कुछ खास बातें।

वर्कला की खासियत क्या है?

वर्कला बीच और क्लिफ्स ये भारत का इकलौता ऐसा समुद्री किनारा है जहां समुद्र के साथ-साथ ऊंची क्लिफ्स (चट्टानें) भी हैं, जो इसे बेहद खास बनाती हैं। यहां खड़े होकर समुद्र की लहरों को नीचे देखने का मजा ही कुछ और है। ये जगह कम लोगों को ही पता है इसलिए यहां कम भीड़, ज्यादा शांति होती है। मानसून में जहां बाकी टूरिस्ट प्लेस भीड़ से भर जाते हैं, वहीं वर्कला शांत और सुकूनभरा रहता है। सबसे खास बात तो ये कि ये बजट फ्रेंडली भी है। यहां आपको सस्ते गेस्टहाउस से लेकर सुंदर होमस्टे और कैफे मिल जाएंगे जो आपके बजट को जरा भी नहीं हिलाएंगे। वर्कला को एक हेल्थ एंड हीलिंग डेस्टिनेशन भी माना जाता है। यहां आयुर्वेदिक मसाज, योग रिट्रीट्स और मेडिटेशन सेंटर्स भी हैं।

वर्कला में क्या-क्या देंखें?

वर्कला में यहां का बीज देखने लायक है। ये समुद्र तट शांत, साफ और बेहद खूबसूरत है। मानसून में यहां लहरें काफी तेज होती है इसलिए यहां स्विमिंग करने से परहेज करें। लेकिन चट्टानों पर बैठकर समुद्र की गूंज और बारिश की बूंदों का मजा जरूर लें। क्लिफ वर्कला की सबसे खास चीज है। ये एक नेचुरल चट्टान है जो समुद्र के किनारे ऊंचाई पर स्थित है। यहां से सनसेट का नजारा मंत्रमुग्ध कर देता है।

यहां आप जनार्दन स्वामी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं , जो लगभग 2000 साल पुराना है। मानसून में यहां की शांति और हरियाली मन को शांति देती है। सिवागिरी मठ जो प्रसिद्ध संत श्री नारायण गुरु की समाधि स्थल है। यहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। मानसून को आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है। वर्कला में कई प्रमाणित आयुर्वेदिक सेंटर हैं जहा थकान मिटाने वाली थेरेपीज मिलती हैं।

वर्कला में बजट में होटल और होमस्टे

वर्कला में आपको हर बजट के मुताबिक, ठहरने की सुविधा मिलती है। यहां आपको होमस्टे और गेस्टहाउस 500 से 1000 रुपये के पर पर्सन मिल जाएंगे। बीच साइड कैफे हैं, जहां आप काफी कम प्राइस में खाना खा सकते हैं।

मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगा लें इन 3 चीजों का रस, स्किन से दाग-धब्बे होंगे दूर

गर्मियों में स्किन का खास ध्यान रखना पड़ता है। धूल-मिट्टी, धूप और प्रदूषण के कारण स्किन खराब होने लगती है और चेहरा डल लगने लगता है। गर्मियों में मुलतानी मिट्टी के साथ आप कुछ चीजों को मिलाकर फेस पैक बना सकते हैं जिससे आपकी त्वचा का निखार बरकरार रहेगा।

हेल्दी स्किन के लिए हम कई सारे प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं पर मार्केट में मिलने वाले अधिकतर प्रोडक्ट्स में केमिकल होता है, जिससे इंस्टेंट निखार तो दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान भी हो सकते हैं। ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से भी त्वचा से भी स्किन का ग्लो को कम हो सकता है और अन्य स्किन प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। हमारी दादी-नानी के समय से मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी लोग मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं। जो स्किन का ऑयल कंट्रोल करती है और चेहरे पर निखार को बरकरार रखती है।

मुल्तानी मिट्टी में एक्सफोलिएटिंग गुण होते हैं जो चेहरे से पिगमेंटेशन, दाग-धब्बों और मुहांसों को कम करने में मदद करते है, पर अगर आप मुल्तानी मिट्टी में ये 3 चीजें मिलाकर लगा लेंगे तो आपको इसके दोगुने फायदे होंगे। तो चलिए जानते हैं इस फेस पैक को कैसे बनाया जाए और इसके क्या-क्या फायदे हैं

मुल्तानी मिट्टी से आता है त्वचा में निखार

मुल्तानी मिट्टी क्लींजर और एक्सफोलिएटर का काम करती है। इसका रोजाना इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा से जुड़ी समस्याएं कम हो जाएंगी। यह त्वचा की पोर्स को साफ करती है, एक्ट्रा ऑयल कम होता है, डेड स्किन सेल्स कम होते हैं, मुहांसे भी कम होते हैं और त्वचा का निखार बरकरार रहता है।

मुल्तानी मिट्टी और आलू का रस

मुल्तानी मिट्टी और आलू का रस स्किन के लिए फायदेमंद होता है। इस फेस पैक को बनाने के लिए एक आलू को कद्दूकस करके रस निकाल लें, फिर उसमें मुल्तानी मिट्टी को मिला दें। इस पेस्ट को चेहरे पर 15-20 मिनट के लिए लगाकर रखें फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। आप देखेंगे की आपकी स्किन ग्लोइंग और स्मूद हो जाएगी।

मुल्तानी मिट्टी और टमाटर का रस

मुल्तानी मिट्टी के साथ टमाटर का रस मिलाने से त्वचा को कई लाभ हो सकते हैं। टमाटर का रस त्वचा को एक्सफोलिएट करने और दाग-धब्बों को हटाने में हेल्प करता है और मुल्तानी मिट्टी त्वचा से एक्सट्रा तेल और गंदगी को निकालने में मदद करता है। इससे टैनिंग भी रिमूव होती है और चेहरे का निखार बरकरार रहता है।

मुल्तानी मिट्टी और नींबू का रस

मुल्तानी मिट्टी और नींबू का रस त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है। इस फेस पैक को लगाने से टैनिंग, पिंपल्स दूर होते हैं जो स्किन को ग्लोइंग बनाते है और झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं।

त्वचा का निखार बरकरार रखने के लिए आपको ये घरेलू नुस्खे जरूर अपनाने चाहिए इससे गर्मी के मौसम में स्किन से जुड़ी सारी समस्याएं जैसे टैनिंग, ड्राइनेस, दाग-धब्बों, मुहांसो से राहत मिलेगी और चेहरा बेदाग लगेगा।

71 देशों की एआई प्रतिस्पर्धा में भारत चौथे स्थान पर, डिजिटल प्रदर्शन में जर्मनी समेत इन देशों को पछाड़ा

'स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी' (एसआईडीई) 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया की पांचवीं सबसे अधिक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। सीएचआईपीएस–एआई इंडेक्स में भारत, चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस एआई प्रतिस्पर्धा में 71 देश शामिल हैं। डिजिटल प्रदर्शन में भारत ने जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के व्यापार में 328 अरब अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। यह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एआई टैलेंट पूल का घर बन चुका है।

'स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी' (एसआईडीई) 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया की पांचवीं सबसे अधिक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। सीएचआईपीएस-एआई इंडेक्स में भारत, चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस एआई प्रतिस्पर्धा में 71 देश शामिल हैं। डिजिटल प्रदर्शन में भारत ने जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के व्यापार में 328 अरब अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। यह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एआई टैलेंट पूल का घर बन चुका है।

एआई का उपयोग, 72% लोग विकासशील देशों में

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब एआई का उपयोग करने वाले 72% लोग विकासशील देशों में हैं, जबकि भारत और चीन मिलकर दुनिया में एआई अपनाने का लगभग दो-पांचवां हिस्सा रखते हैं। रि जनरेटिव एआई इतिहास की किसी भी पूर्व तकनीक की तुलना में सबसे तेज़ी से अपनाई जाने वाली तकनीक बन गई है। इसकी लॉंचिंग के तुरंत बाद ही यह विकासशील देशों में तेजी से लोकप्रिय हो गया है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की संरचना में बड़ा परिवर्तन आया है। दुनिया की शीर्ष पांच डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में अब तीन देश — चीन, सिंगापुर और भारत — इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से हैं, जो पारंपरिक उत्तरी अटलांटिक देशों के साथ एक नए त्रिध्रुवीय डिजिटल व्यवस्था के उभरने का संकेत देता है।

डिजिटल भरोसे को मजबूत बनाना चुनौती

प्रमोद भसीन, चेयरपर्सन, आईसीआरआईआर के मुताबिक, भारत ने कनेक्टिविटी, उद्यमिता और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मजबूत नींव तैयार की है। विकास का अगला चरण इस बात पर निर्भर करेगा कि हम एआई का कितना प्रभावी उपयोग कर पाते हैं, नवाचार क्षमताओं को कितना आगे बढ़ाते हैं। जरूरी बात ये भी है कि हम डिजिटल भरोसे को कितना मजबूत बना पाते हैं। भारत ने वैश्विक रैंकिंग में आठवें स्थान से बढ़कर पांचवां स्थान हासिल किया है, जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच उसकी तेज़ डिजिटल प्रगति को दर्शाता है। वहीं, एआई इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान - अमेरिका, चीन और सिंगापुर के बाद - उसे एक उभरती हुई वैश्विक एआई शक्ति के रूप में इसके उभरने की पुष्टि करता है।

दूरदर्शी नीतिगत तैयारी की आवश्यकता

डॉ. दीपक मिश्रा, डिस्टिंग्विश्ड विजिटिंग प्रोफेसर, आईसीआरआईईआर ने कहा, भारत अब केवल डिजिटल तकनीक अपनाने वाला देश नहीं रहा, बल्कि एक डिजिटल लीडर के रूप में उभरा है। इस बड़े पैमाने की प्रगति को

लगातार नवाचार और उत्पादकता में बदलने के लिए मजबूत संस्थानों, अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक निवेश और दूरदर्शी नीतिगत तैयारी की आवश्यकता होगी। भारत का डिजिटल बदलाव अब तेजी से एआई अपनाने, फिनटेक नवाचार और तेज़ी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए आगे बढ़ रहा है। देश सॉफ्टवेयर, आईटी सेवाओं और क्लाउड आधारित समाधानों जैसी डिजिटल सेवाओं का वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्यातक बनकर उभरा है। कम-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, भारत ने डिजिटल सेवाओं के व्यापार में लगभग 328 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा हासिल किया है।

बेहतर व्यावसायीकरण के रास्ते विकसित करना

भारत अब सिर्फ एक बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था नहीं रहा। यह दुनिया की सबसे प्रभावशाली एआई अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है। प्रोसस में हम भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को एक दीर्घकालिक नवाचार साझेदार के रूप में समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सेहराज सिंह, वाइस प्रेसिडेंट, ग्रुप कॉरपोरेट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी, प्रोसस ने यह बात कही है। भारत का अगला चरण कई महत्वपूर्ण फायदों और स्पष्ट अवसरों का संयोजन है। इसमें अमेरिका के बाद दुनिया में एआई प्रतिभा का दूसरा सबसे बड़ा समूह, बड़े पैमाने पर तकनीकी उपयोगकर्ता आधार और मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इन क्षमताओं को सतत मूल्य निर्माण में बदलने के लिए कंप्यूटिंग संसाधनों तक बेहतर पहुंच, जोखिम पूंजी को सक्रिय रूप से जुटाना, और विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स तथा उद्योग के बीच बेहतर व्यावसायीकरण के रास्ते विकसित करना जरूरी होगा।

कुछ चुनिंदा देशों और कंपनियों तक सीमित

रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि हालांकि एआई का उपयोग दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अत्याधुनिक एआई अवसंरचना — जैसे उन्नत चिप्स, कंप्यूटिंग क्षमता और बड़े भाषा मॉडल — अब भी कुछ चुनिंदा देशों और कंपनियों तक सीमित है। आने वाले दशक में भारत की प्रतिस्पर्धी स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपनी घरेलू एआई क्षमताओं को कितनी अच्छी तरह विकसित करता है और साथ ही अपने एप्लिकेशन-लेयर की मजबूती का कितना प्रभावी उपयोग करता है। हालांकि डिजिटलीकरण ने अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में बदलाव लाकर विकास को बढ़ावा दिया है। उन्हें कई लाभ पहुंचाए हैं, लेकिन इसके साथ नए जोखिम और छिपी हुई लागतें भी सामने आई हैं। ऑनलाइन वित्तीय अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी में तेज़ी से वृद्धि हुई है और अब ये देश में सबसे अधिक रिपोर्ट किए जाने वाले अपराधों में शामिल हैं। इसके अलावा, डिजिटल बहिष्करण का जोखिम और बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी गंभीर चिंता के रूप में उभरकर सामने आई हैं।

अपराध की रोकथाम के लिए पर्याप्त निवेश हो

रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि तेज़ डिजिटलीकरण के साथ साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पर्याप्त निवेश भी आवश्यक है। साथ ही, विकासशील देशों के पास उन पर्यावरणीय रूप से हानिकारक रास्तों से बचने का अवसर है, जिन्हें कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने डिजिटलीकरण के दौरान अपनाया था। साइड 2026 रिपोर्ट में उन्नत सीएचआईपीएस फ्रेमवर्क— कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट और सस्टेन का उपयोग किया गया है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसे विशेष रूप से इस बात को समझने के लिए बनाया गया है कि उभरती अर्थव्यवस्थाएँ एआई के युग में कैसे आगे बढ़ रही हैं। यह विस्तारित फ्रेमवर्क उन देशों को कवर करता है, जो वैश्विक जीडीपी के 96%, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के 93% और दुनिया की 91% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे यह अब तक का सबसे व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्था बेंचमार्क बन गया है।

साइड रिपोर्ट 2026 के प्रमुख निष्कर्ष

भारत ने 2025 में आठवें स्थान से बढ़कर 2026 में पांचवें स्थान हासिल किया है, जो कनेक्टिविटी, एआई अपनाने और नवाचार क्षमताओं में सुधार को दर्शाता है।

भारत स्टैंडअलोन एआई इंडेक्स में चौथे स्थान पर है। कई प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं से आगे है। एआई परफॉर्मेंस में भारत सिर्फ़ अमेरिका, चीन और सिंगापुर से पीछे है, और जर्मनी, फ्रांस, यूके, जापान और कनाडा से आगे है।

दुनिया के 72% एआई उपयोगकर्ता अब विकासशील देशों में हैं

जनरेटिव एआई इतिहास की सबसे तेजी से फैलने वाली डिजिटल तकनीक बन गई है। चीन और भारत में इतने एआई उपयोगकर्ता हैं कि वे मिलकर (अमेरिका को छोड़कर) सभी विकसित देशों से अधिक हैं। दोनों मिलकर दुनिया भर के एआई यूज़र्स का लगभग दो-पांचवां हिस्सा बनाते हैं।

दुनिया की शीर्ष पांच डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से तीन — चीन, सिंगापुर और भारत — इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से हैं। यह पारंपरिक नॉर्थ अटलांटिक केंद्रित व्यवस्था से हटकर एक त्रिध्रुवीय डिजिटल व्यवस्था के उभरने का संकेत देता है।

भारत ने डिजिटल रूप से दी जाने वाली सेवाओं के व्यापार में 328 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा दर्ज किया है। भारत डिजिटल रूप से दी जाने वाली सेवाओं (सॉफ्टवेयर, आईटी सेवाओं और क्लाउड समाधानों) का दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन गया है। हालांकि यह एक कम-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। भारत ब्रिक्स डिजिटल्ली डिलीवर्ड सर्विसेज में ₹50% का योगदान देता है।

भारत के पास वैश्विक एआई उपयोगकर्ताओं का लगभग 26% हिस्सा है, लेकिन वैश्विक प्राइवेट एआई निवेश में उसका हिस्सा केवल 1% है, जो एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है। एआई टैलेंट के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन दीर्घकालिक वेंचर कैपिटल और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वह समान स्तर पर नहीं है- जो एक चुनौती भी है और एक अवसर भी।

अत्याधुनिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक स्तर पर केंद्रित बना हुआ है

हालांकि एआई का उपयोग दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, लेकिन उन्नत चिप्स, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े भाषा मॉडल अभी भी कुछ ही देशों और कंपनियों के समूह में केंद्रित हैं।

पैमाने को नवाचार में बदलना भारत की सबसे बड़ी चुनौती है

भारत की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जोखिम पूंजी जुटाने, कंप्यूट एक्सेस का विस्तार करने, विश्वविद्यालय-स्टार्टअप संबंधों को मज़बूत करने और एआई के व्यावसायीकरण के रास्ते बनाने पर निर्भर करती है।

डिजिटलीकरण से जुड़े जोखिमों और लागतों, जैसे साइबर अपराध, डिजिटल बहिष्कार और पर्यावरणीय स्थिरता को नियंत्रित करने के लिए अधिक ध्यान और प्रभावी नीतिगत उपायों की आवश्यकता है।

नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के ट्रंप, इजराइली प्रधानमंत्री को मुंह पर कह दिया पागल

पागल, अहसान फरामोश...बेंजामिन नेतन्याहू पर इतना क्यों भड़के हैं अमेरिका के राष्ट्रपति?

वॉशिंगटन, एजेंसी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इस दौरान ट्रंप नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के। उन्होंने लेबनान पर इजराइली हमलों को लेकर भारी नाराजगी जाहिर की और मुंह पर नेतन्याहू को पागल तक कह दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

न्यूज वेबसाइट Axios की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ फौरन हमले रोकने की मांग करते हुए ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू को जेल जाने से बचने के लिए उनका अहसानमंद होना चाहिए। उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि लेबनान की राजधानी पर बमबारी की धमकियां इजराइल को दुनिया में और ज्यादा अलग-थलग कर देंगी।

रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को इस बात की चिंता थी कि लेबनान में जारी हमले मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की कोशिशों और ईरान के साथ चल रही बातचीत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने नेतन्याहू से फोन पर सीधे बात की और अपनी नाराजगी जाहिर की।

'तुम तो बिल्कुल ही पागल हो'

इस रिपोर्ट में बातचीत से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप ने बातचीत के दौरान नेतन्याहू को पागल तक दिया साथ ही दावा किया कि उन्होंने उन्हें को राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों से निपटने में मदद करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके खिलाफ चल रहा भ्रष्टाचार का मुकदमा भी शामिल है। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। अगर मैं न होता, तो तुम अब तक जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है। इसी वजह से हर कोई इजराइल से भी नफरत करता है।

नेतन्याहू पर भड़के ट्रंप

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू के प्रति बेहद सख्त लहजे में बात की। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि इजराइली प्रधानमंत्री की मौजूदा नीतियों के कारण दुनिया भर में इजराइल की छवि प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप काफी गुस्से में थे और उन्होंने नेतन्याहू पर चिल्लाते हुए पूछा तुम आखिर कर क्या रहे हो?। दरअसल वॉशिंगटन में इस बात को लेकर चिंता है कि इजराइल की तरफ से लेबनान पर हो रही कार्रवाई ने ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने की वॉशिंगटन की कोशिशों को खतरे में डाल दिया है। क्योंकि तेहरान ने समझौते के लिए लेबनान में सीजफायर को एक शर्त के तौर पर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक फोन पर बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू पर काफी दबाव बनाया और नेतन्याहू ने बस 'ठीक है, ठीक है' कहते रहे।

ट्रंप ने हिज्बुल्लाह पर हमले रोकने को कहा

हाल ही में इजराइल ने दक्षिणी बेरुत में आतंकवादियों पर हवाई हमलों के आदेश दिए थे। इजराइल के इस कदम के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत से पीछे हटने की धमकी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप नेतन्याहू से फोन पर बातचीत के दौरान काफी गुस्से में थे और उन्होंने नेतन्याहू से हिज्बुल्लाह पर किए जा रहे हमलों को फौरन रोकने को कहा।

वॉशिंगटन, एजेंसी। ईरान के साथ युद्धविराम टूटने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर जमकर भड़ास निकाली है। ट्रंप ने एक फोन कॉल के दौरान गुस्से में नेतन्याहू को 'पागल' तक कह दिया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेताओं के बीच हुई इस गोपनीय बातचीत की जानकारी व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने मीडिया तक पहुंचा दी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई ट्रंप नेतन्याहू से नाराज हैं और अगर हां, तो इसकी वजह क्या है? अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक, फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने लेबनान में हुए हमले को लेकर नेतन्याहू पर नाराजगी जाहिर की। ट्रंप ने कहा, "बीबी, तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया, लेकिन तुम अब भी यह बात नहीं समझ रहे हो।" ट्रंप ने आगे कहा- पूरी दुनिया तुमसे नाराज है। लोग तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हारी वजह से लोग इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। दुनिया की कूटनीति इस तरह नहीं चलती।

ईरान के साथ युद्धविराम की राह में नेतन्याहू रोड़ा बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जब बातचीत पटरी पर लौटती है, तब इजराइल कुछ ऐसा कर देता है, जिसके कारण ईरान बातचीत से पीछे हट जाता है। ताजा मामला लेबनान पर हमला को लेकर है। ईरान का कहना है कि सीजफायर के बावजूद इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है। इस हमले में आम नागरिकों की मौत हो रही है। ट्रंप भी इस फैक्ट्स से सहमत हैं। इसी कारण उन्होंने नेतन्याहू को फटकार लगाई।

ईरान युद्ध की शुरुआत में नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कहा गया कि युद्ध के बाद ईरान में तख्तापलट हो जाएगा। कुर्द्स को भी साधने की बात नेतन्याहू ने कही, लेकिन जब लड़ाई की शुरुआत हुई तो ईरान की जनता ने अमेरिका और इजराइल से मुंह मोड़ लिया। इसके कारण अमेरिका को अरब में काफी नुकसान हुआ। अमेरिका अब किसी तरह ईरान के साथ एक सम्मानजनक समझौता चाहता है।

मुनीर के दावे एक तरफ! पाकिस्तान में हर दिन 2 से ज्यादा सैनिकों की हत्या कर रहे आतंकवादी

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान में आतंकवादी हर दिन औसतन दो से अधिक सैनिकों की हत्या कर रहे हैं। यह खुलासा पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में हुआ है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉनफ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज (PICSS) द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, मई महीने में आतंकवादियों ने 68 जवानों की हत्या कर दी। इस दौरान 71 आम नागरिकों की भी जान गई। वहीं, मई में हुए आतंकी हमलों में 37 जवान घायल हुए।

सेना को लेकर यह रिपोर्ट ऐसे वक्त सामने आई है, जब पिछले दिनों पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकियों के कमर तोड़ने का दावा किया था।

रिपोर्ट के अनुसार, मार्च और अप्रैल में अपेक्षाकृत शांत रहने वाले आतंकियों ने मई में फिर से हिंसा तेज कर दी। पूरे पाकिस्तान में कुल 128 आतंकी हमले दर्ज किए गए। इस दौरान आतंकवादियों ने चार आत्मघाती हमले भी किए।

मई 2026 में बलूचिस्तान आतंक से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांत के तौर पर सामने आया। इस प्रांत में 71 आतंकी हमले दर्ज किए गए, जबकि अप्रैल में यह संख्या 34 थी। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो यह 109 फीसदी की बढ़ोतरी को दिखाता है। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वाह और राजधानी इस्लामाबाद आतंकी हमले से प्रभावित रहा है।

बलूचिस्तान में आतंकियों ने सबसे ज्यादा अपहरण की घटना को अंजाम दिया है। मई के महीने में पूरे देश में अपहरण की कुल 54 घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें से 52 घटनाएं अकेले बलूचिस्तान में हुईं।

दूसरी ओर, पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने जवाबी अभियानों के दौरान मई महीने में 270 आतंकवादियों को मार गिराया। PICSS के रिकॉर्ड के अनुसार, इस अवधि में सुरक्षा बलों ने 270 आतंकियों को ढेर किया और 15 अन्य को गिरफ्तार किया। वहीं, कुछ आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा 128 आतंकवादी पूर्व फाटा क्षेत्र में मारे गए। इसके अलावा, खैबर पख्तूनख्वा के अन्य हिस्सों में 62 और बलूचिस्तान में 71 आतंकियों को मार गिराया गया। पंजाब प्रांत में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अल-कायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन सक्रिय हैं। हाल ही सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने इन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान से खत्म करने की घोषणा की थी।

न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने किया यहूदियों का अपमान? परेड में न शामिल होने पर खड़ा हुआ विवाद

न्यूयॉर्क, एजेंसी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार वो यहूदी समाज का अपमान को लेकर चर्चा में हैं। ममदानी रविवार को आयोजित इजराइल डे परेड में शामिल नहीं हुए इसको लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। जिससे राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई।

दशकों पुरानी राजनीतिक परंपरा को तोड़ते हुए जोहरान ममदानी ने 31 मई को इजराइल के सम्मान में आयोजित होने वाली सालाना परेड में हिस्सा नहीं लिया। दशकों से यह परेड न्यूयॉर्क के मेयर, गवर्नर और अन्य बड़े नेताओं के लिए एक अहम राजनीतिक कार्यक्रम मानी जाती रही है, लेकिन ममदानी ने अपने फिलिस्तीनी समर्थक रुख के चलते इसमें शिरकत नहीं की। इस परेड में शामिल न होने वाले ममदानी पहले मेयर हैं।

फिलिस्तीन के समर्थक हैं ममदानी

दरअसल जोहरान ममदानी ने फिलिस्तीन के समर्थक हैं और इस परेड में इजराइल को सम्मानित किया जा रहा था जिस वजह से ममदानी परेड में मौजूद नहीं रहे। यह परेड हर साल इजरायइ दिवस पर मनाई जाती है, जहां 1948 में यहूदी देश के रूप में हुए इजराइल के गठन का जश्न मनाया जाता है।

चुनाव प्रचार के दौरान किया था इनकार

ममदानी ने इस परेड को लेकर अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था कि वो इस परेड में शामिल नहीं होंगे। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममदानी ने कहा कि वो अपने विचार इजराइल सरकार को लेकर पहले ही साफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव प्रचार के समय ही उन्होंने यह बात कह दी थी कि वो इजराइल डे परेड में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि परेड के शांतिपूर्ण संचालन के लिए न्यूयॉर्क पुलिस की ओर से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।

यहूदी समुदाय ने जताई नाराजगी

जोहरान ममदानी के परेड में न शामिल होने के निर्णय की शहर में जमकर निंदा हुई। लॉन्ग आइलैंड के हैम्पटन सिनेगॉग के हेड रब्बी मार्क श्नायर ने ममदानी के फैसले को न्यूयॉर्क के यहूदी समुदाय का अपमान बताया। उन्होंने कहा 'अगर आप परेड में नहीं आना चाहते तो घर पर ही रहें। हमें आपकी जरूरत नहीं है'। वहीं न्यूयॉर्क सिटी की पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश जो यहूदी समुदाय से आती हैं वो परेड में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि ममदानी का परेड में हिसेसा न लेना उनका अपना फैसला है और परेड में गर्व से शामिल होना यह मेरा फैसला है।

'नकबा' को याद कर वीडियो जारी किया

जोहरान ममदानी के परेड में न शामिल होने पर विवाद इसलिए भी बढ़ा क्योंकि दो सप्ताह पहले मेयर कार्यालय की ओर से 'नकबा' को याद करते हुए एक वीडियो जारी किया गया था। 'नकबा' शब्द 1948 के अरब-इजराइल युद्ध के दौरान लाखों फिलिस्तीनियों के विस्थापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो में एक ऐसी फिलिस्तीनी महिला की कहानी दिखाई गई है जो 9 साल की उम्र में विस्थापित हो गई थी। इस कदम की कई यहूदी संगठनों और इजराइल समर्थकों ने आलोचना की थी। उनका कहना था कि वीडियो में उस दौर में मुस्लिम देशों से विस्थापित हुए यहूदियों और होलोकॉस्ट के बाद यहूदी राष्ट्र की मांग की पृष्ठभूमि का जिक्र नहीं किया गया। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर माने जा रहे ममदानी लंबे समय से फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल को अस्तित्व का अधिकार है, लेकिन वह ऐसे राज्य के पक्ष में नहीं हैं जहां किसी एक समुदाय को विशेष प्राथमिकता मिले, इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि न्यूयॉर्क में यहूदी समुदाय की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है।

शहजाद पूनावाला का दावा, कर्नाटक में कांग्रेस के 'सत्ता के खेल' से ठप प्रशासन, जनता बेहाल

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए उस पर शासन और प्रशासनिक कर्तव्यों की बजाय आंतरिक राजनीतिक संघर्षों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि काफी समय से सत्ता में होने के बावजूद राज्य सरकार अभी भी सत्ता संघर्ष में लगी हुई है, जिसके कारण शासन व्यवस्था से जुड़े मुद्दों की अनदेखी हो रही है। पूनावाला ने कहा कि हमें लगा था कि कर्नाटक में तीन साल से चल रहे इस लगातार सत्ता संघर्ष के बाद अब आखिरकार प्रशासन और शासन व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, लेकिन वे अभी भी सत्ता संघर्ष में लगे हुए हैं।

पूनावाला ने आगे आरोप लगाया कि नागरिक बुनियादी ढांचे, गड्ढों की मरम्मत, जलभराव, आर्थिक ऋण और भ्रष्टाचार जैसे प्रमुख मुद्दों पर राज्य नेतृत्व ने कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में गड्ढों वाली सड़कों, जलभराव, बुनियादी ढांचे, आर्थिक ऋण कम करने और भ्रष्टाचार के लिए अब तक एक भी बैठक नहीं बुलाई गई है। इसके बजाय, इस बात पर बैठकें हो रही हैं कि किसे कौन सा मंत्रिमंडलीय पद मिलेगा।

उन्होंने यह भी दावा किया कि सत्ताधारी दल के भीतर चल रही राजनीतिक बातचीत के कारण प्रशासनिक तंत्र ठप्प हो गया है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। पूनावाला ने कहा कि पूरा प्रशासन ठप्प हो गया है और लोग परेशान हो रहे हैं। ये टिप्पणियां कर्नाटक के सत्ताधारी तंत्र में नेतृत्व समन्वय और मंत्रिमंडल गठन को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच आई हैं। ये चर्चाएं 28 मई को सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद 3 जून को डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह से पहले हो रही हैं।

कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, जहां पार्टी उच्च कमान निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मुख्यमंत्री पद के लिए नामित शिवकुमार के साथ नए मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए बैठक कर रही है। इन बैठकों के दौरान मंत्री पदों और उपमुख्यमंत्री की भूमिका पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा सीबीएसई की ओएसएम का विवाद, जांच की उठी मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका ((PIL) दायर कर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुरू की गई नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM)) प्रणाली पर चिंता जताई है। छात्र संगठन ने मांग की है कि सत्यापन प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए और विवादित मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं की मैन्युअल जांच हो साथ ही पूरी डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के कामकाज की स्वतंत्र जांच कराई जाए।

याचिका में NSUI ने दावा किया गया है कि 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद देशभर के हजारों छात्रों ने अपने अंकों को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। छात्रों ने शिकायत की कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपियां धुंधली थीं, कई पन्ने गायब थे, कई कॉपियां पूरी तरह अपलोड नहीं हुई थीं और कुछ उत्तर पुस्तिकाएं आपस में मेल नहीं खा रही थीं। इसके अलावा कई छात्रों को कम अंक मिले और सत्यापन पोर्टल तक पहुंचने में भी दिक्कतें आईं।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि कक्षा 12वींकी बोर्ड परीक्षा के परिणाम कॉलेज में प्रवेश, छात्रवृत्ति और भविष्य के शैक्षिक अवसरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनका कहना है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी त्रुटि के छात्रों और उनके शैक्षणिक भविष्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। NSUI का कहना है कि इन खामियों के कारण कई विद्यार्थियों को अपेक्षा से काफी कम अंक प्राप्त हुए, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। NSUI ने तर्क दिया कि यदि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में तकनीकी खामियां हैं तो उसका खामियाजा छात्रों को नहीं भुगतना चाहिए।

याचिका में की ये मांग

NSUI अध्यक्ष विनोद झाखर के माध्यम से दायर की गई जनहित याचिका में कोर्ट से उन छात्रों को क्षतिपूर्ति अंक देने का निर्देश देने की मांग की गई है जिनकी उत्तर पुस्तिकाएं गुम थीं, धुंधली थीं या गलत तरीके से मूल्यांकित की गई थीं। याचिका में कहा गया है कि परिणाम घोषित होने के बाद CBSE ने कई बार सार्वजनिक संदेश जारी किए थे। इसमें बोर्ड ने माना था कि उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने वाले पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें आई थीं, जिसके कारण समय सीमा को कई बार बढ़ाना पड़ा।

याचिका के मुताबिक करीब 3। 87 लाख उत्तर पुस्तिकाओं से जुड़े 1। 27 लाख से अधिक आवेदन छात्रों ने अपनी जांची हुई कॉपियों की स्कैन कॉपी लेने के लिए किए थे। NSUI का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन यह दिखाते हैं कि नई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को लेकर छात्रों में काफी चिंता है। याचिका में यह भी बताया गया है कि कई छात्रों ने धुंधली या गायब स्कैन कॉपी, बिना जांचे उत्तर और अन्य मूल्यांकन संबंधी समस्याओं की शिकायत की है।

'समस्या सिस्टम की खामियों की वजह से पैदा हुई'

जनहित याचिका में कहा गया है कि जिन छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग और मूल्यांकन सही तरीके से हुआ है, उन्हें अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है, जबकि जिन कॉपियों में तकनीकी खराबी है उनके साथ समस्या हो रही है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि यह नुकसान उन छात्रों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह समस्या सिस्टम की खामियों की वजह से पैदा हुई है।

इसके अलावा कहा गया है कि मौजूदा शिकायत निवारण व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, क्योंकि छात्रों के पास सीमित डिजिटल विकल्प हैं और स्कैन कॉपी को लेकर विवाद होने पर मैनुअल जांच का कोई मजबूत विकल्प नहीं है। NSUI कोर्ट से मांग की है कि सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को एक महीने और बढ़ाया जाए। साथ ही जिन मामलों में छात्र स्कैन कॉपी या मूल्यांकन पर सवाल उठा रहे हैं, वहां कॉपियों की मैन्युअल और भौतिक जांच की भी अनुमति दी जाए।

स्वतंत्र जांच की मांग

याचिका में कहा गया है कि OSM प्रणाली में जो अनियमितताएं, तकनीकी खामियां और कमियां सामने आई हैं, उनकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट से मांग की गई है कि CBSE को भविष्य की डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था के लिए सही सुरक्षा उपाय और स्पष्ट दिशा निर्देश बनाने के निर्देश दिए जाएं। NSUI ने यह भी मांग की है कि जिन मामलों में छात्रों की कोई गलती नहीं है, लेकिन उनकी उत्तर पुस्तिकाएं खो गई हैं, धुंधली हैं या गलत तरीके से जांची गई हैं, उन छात्रों को मुआवजे के रूप में अतिरिक्त अंक दिए जाएं।

थैरेपी पर नुसरत ने बताया नजरिया, बॉलीवुड के ये सितारे भी रहे डिप्रेशन का शिकार

फिल्म 'छोरी 2' में नजर आईं नुसरत भरुचा ने हाल ही में कहा कि एक्टर्स को थैरेपी लेनी चाहिए, खुद को हील करना चाहिए। बॉलीवुड में भी कई एक्टर्स हैं, जो जिंदगी के किसी दौर में डिप्रेशन का शिकार हुए। जानिए, किस सेलिब्रिटी ने अपने डिप्रेशन पर बात की, इससे उबरने की कोशिश।

हाल ही में एक्ट्रेस नुसरत भरुचा ने अमर उजाला संवाद के मंच पर सोशल मीडिया के बुरे असर पर बात की। साथ ही बताया कि कई एक्टर्स को अपने रोल से बाहर आने के लिए थैरेपी की जरूरत पड़ती है। थैरेपी सिर्फ किसी किरदार से बाहर आने में ही मदद नहीं करती है, ये डिप्रेशन को ठीक करने में भी मददगार है। जानिए, ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जो कभी डिप्रेशन का शिकार रहे और बाद में थैरेपी, फैमिली सपोर्ट से ठीक हो गए।

दीपिका पादुकोण

साल 2015 में दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन को लेकर बात की। साथ ही एक संस्था भी शुरू की, जो डिप्रेशन से लड़ने में लोगों की मदद करती है, मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस फैलाती है। दीपिका अपनी कोशिशों, थैरेपी और फैमिली सपोर्ट के कारण डिप्रेशन से उबर पाईं और आज एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं।

हनी सिंह

हनी सिंह साल 2016 में डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हुए। हाल ही में इस सिंगर ने खुलकर अपने डिप्रेशन पर बात की। हनी सिंह पर बनीं एक डॉक्यूमेंट्री में भी इस बात का जिक्र किया गया। हनी सिंह कहते हैं कि वह तो इस समस्या के कारण मरने के कगार पर पहुंचे गए थे लेकिन डॉक्टर की दवा, थैरेपी और अपनों के साथ ने उन्हें एक नया जीवन दिया है।

इमरान खान

पिछले साल आमिर खान के भांजे इमरान खान ने भी खुलकर अपने डिप्रेशन पर बात की। एक्टर का कहना था कि पर्सनल कारणों से वह डिप्रेशन, एंग्जायटी का शिकार हुए। साथ ही इमरान खान ने बताया कि वह इस समस्या को ठीक करने के लिए थैरेपी भी ले रहे हैं।

अनुष्का शर्मा

साल 2015 में अनुष्का शर्मा ने अपनी एंग्जायटी के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यू को सीरियसली लेना चाहिए। अनुष्का का मानना है कि बाकी बीमारियों की तरह ही मेंटल हेल्थ पर डिस्कशन होना चाहिए।

सेलिना जेटली की बढ़ी मुश्किलें, पति-ससुर ने भेजा नोटिस, झूठे आरोपों और मीडिया ट्रायल पर आपत्ति

अभिनेत्री सेलिना जेटली की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तलाक और बच्चों की कस्टडी को लेकर चल रहे विवादों के बीच उन्हें पति पीटर हाग और ससुर डीआई वोल्फगैंग जे. हाग ने दो अलग-अलग कानूनी नोटिस भेजे हैं। मुंबई स्थित विधि फर्म सेमवाल एंड कंपनी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ये नोटिस सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कई मीडिया माध्यमों में प्रसारित की जा रही उन बातों के संबंध में जारी किए गए हैं, जिन्हें हाग परिवार ने भ्रामक, असत्य और मानहानिकारक बताया है। जानकारी के अनुसार, पहला नोटिस पीटर हाग के पिता डीआई वोल्फगैंग जे. हाग की ओर से भेजा गया है, जबकि दूसरा नोटिस स्वयं पीटर हाग ने अपने और अपने तीन नाबालिग बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए जारी किया है। परिवार का कहना है कि पिछले कुछ समय से उनके खिलाफ सार्वजनिक मंचों पर कई ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनका वास्तविक तथ्यों से कोई संबंध नहीं है।

नोटिस में उल्लेख किया गया है कि पीटर हाग और सेलिना जेटली के बीच वैवाहिक विवाद और बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामले वर्तमान में ऑस्ट्रिया की अदालतों में विचाराधीन हैं। परिवार का आरोप है कि न्यायिक प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद इस मामले से जुड़े कई बयान, इंटरव्यू और सोशल मीडिया पोस्ट सार्वजनिक रूप से साझा किए गए, जिनमें हाग फैमिली को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए।

हाग फैमिली का कहना है कि उन्होंने लंबे समय तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने से परहेज किया, क्योंकि वे चाहते थे कि पारिवारिक और बच्चों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों का समाधान कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हो। हालांकि, उनके अनुसार लगातार लग रहे सार्वजनिक आरोपों और मीडिया में उनके प्रसार के चलते अब कानूनी कदम उठाना जरूरी हो गया था।

नोटिस में उन आरोपों का विशेष रूप से खंडन किया गया है, जिनमें पीटर हाग को हिंसक, अपमानजनक, भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करने वाला या डराने-धमकाने वाला व्यक्ति बताया गया है। इसके अलावा, बच्चों को छिपाने, उनकी सोच को प्रभावित या ब्रेनवॉश करने, उत्पीड़न करने और धर्म से जुड़े कुछ आरोपों को भी परिवार ने पूरी तरह निराधार बताया है।

हाग फैमिली ने सबसे अधिक चिंता बच्चों की प्राइवेसी और मानसिक स्थिति को लेकर जताई है। उनका कहना है कि लगातार सार्वजनिक चर्चाओं, तस्वीरों को पोस्ट करने और निजी मामलों को मीडिया में लाने से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उनका मानना है कि बच्चों से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता और गोपनीयता के साथ संभाला जाना चाहिए और सार्वजनिक बहस या मीडिया ट्रायल का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। नोटिस में यह भी कहा गया है कि कथित रूप से प्रसारित की गए कुछ कंटेंट मानहानि, निजता के उल्लंघन और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की श्रेणी में आ सकते हैं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com